

निजी बसों से डीटीसी कर्मचारियों के भविष्य पर चिंता 8000 चालक काम न होने से अन्य कार्यों में लगे कर्मचारियों की मांग: डीटीसी अपनी बसें चलाए

डीटीसी कर्मचारी निजी कंपनियों की ओर से लाई जा रही बसों से अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। वे मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से डीटीसी द्वारा अपनी बसें चलाने की मांग कर रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि निजी कंपनियों के माध्यम से बसें चलाने से डीटीसी और कर्मचारियों का भला नहीं होगा। 8000 चालक काम न होने से अन्य कार्यों में लगे हैं, जिससे उनकी नौकरी पर खतरा मंडरा रहा है।

परिवहन विशेष न्यून

नई दिल्ली। डीटीसी में प्राइवेट कंपनियों की ओर से बसें लाई जाती रही तो डीटीसी के कर्मचारियों को रोजगार कैसे मिलेगा? डीटीसी कर्मचारियों को अपने भविष्य को लेकर यह चिंता सता रही है। दिल्ली सरकार ने कुछ दिन पहले डिस्ट्रिक्ट की बसों को डीटीसी को सौंपने का फैसला लिया है। इसके बाद से कर्मचारियों की मांग तेज हो गई है।

कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से मांग की है कि सरकार निजी कंपनियों की जगह अपनी बसें लेकर आए। उनकी मांग तो कंपनियों के माध्यम से बसें चलाने से न ही डीटीसी और न ही कर्मचारियों का भला होने वाला है।

काम न होने से डीटीसी में इस समय 8000 के करीब चालक बसें न चलकर अन्य काम में लगाए गए हैं। इन कर्मचारियों को डर यह सता रहा है कि अगर डीटीसी अपनी बसें लेकर नहीं आती है तो उनकी नौकरी ज्यादा दिन चल पाएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है।

पिछले कुछ सालों की स्थिति का आंकलन करें तो 2025 ऐसा साल रहा है जब दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) में एक साल में ही 5000 से अधिक बस



चालकों के पास बस चलाने का काम काम नहीं रहा। दरअसल उम्र पूरी होने के कारण इस साल डीटीसी की 2500 से अधिक बसें सड़कों से हट गई हैं। ये बसें डीटीसी स्वयं चला रही थी।

इन पर 5000 के करीब चालक लगे हुए थे। डीटीसी ने चालकों को बस चलाने की जगह बसों में टिकट जांच आदि काम में लगा रखा है। उधर इस साल डीटीसी में 1400 के करीब नई इलेक्ट्रिक बसें आई हुई हैं। मगर अधिकतर बसें कंपनियों के माध्यम से आई हैं। जिन पर डीटीसी का केवल कंडक्टर होता है चालक कंपनियों के अपने हैं।

दरअसल पूर्व की आप की सरकार के समय में शुरू की गई इस योजना के तहत

सरकार के फैसले के तहत जो व्यवस्था है उसमें प्राइवेट कंपनियों किलोमीटर स्कीम के तहत इलेक्ट्रिक बसें चला रही हैं, उनमें कंडक्टर केवल डीटीसी का है और अन्य सभी व्यवस्थाएं कंपनियों अपने आप देख रही हैं। डीटीसी प्रति किलोमीटर के हिसाब से कंपनियों को भुगतान करती है।

डीटीसी में इस समय लगभग 25 हजार अनुबंधित कर्मचारी हैं और लगभग सात 7 हजार पक्के कर्मचारी हैं। इनमें कुल मिलाकर 8000 के करीब चालक हैं। चालकों में 4500 के करीब अनुबंधित और 3500 के करीब स्थायी हैं।

जानकारों की मानें तो डीटीसी में इस समय करीब 700 बसें हैं। इन पर ही डीटीसी के अपने चालक भी हैं। डीटीसी के

कर्मचारियों का कहना है कि क्लस्टर सेवा के तहत नई आई देवी बसों में कुछ डिपो में कंडक्टर भी निजी कंपनियों के हैं। इन हालातों को लेकर स्थाई और अनुबंधित दोनों तरह के कर्मचारी परेशान हैं।

डीटीसी कर्मचारी एकता यूनियन ने डीटीसी में आ रही प्राइवेट कंपनियों की बसों का कड़ा विरोध किया है। यूनियन का कहना है कि इन बसों में कम वेतन पर कंपनियों ने अपने चालक रखे हुए हैं। यूनियन के अध्यक्ष ललित चौधरी और महामंत्री मनोज शर्मा कहते हैं कि प्राइवेट कंपनियों के कई चालक कम अनुभव हैं, यह एक मुद्दा है, मगर सबसे बड़ा मुद्दा है कि डीटीसी में प्राइवेट कंपनियों के माध्यम से बसें आंगूरी तो डीटीसी के कर्मचारियों का भविष्य कैसे सुरक्षित बचेगा।

इनकी मांग है कि डीटीसी अपनी बसें लाए और अंतरराज्यीय स्तर पर भी चलाए, इससे सरकार और डीटीसी को बहुत मुनाफा भी होगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि सीएम रेखा गुप्ता जरूर उनकी मांग पर सजान लेंगे। वहीं डीटीसी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि डीटीसी ने बसें काम होने के बाद भी किसी कर्मचारी को काम से नहीं हटाया है। चालकों को भी काम दिया हुआ है।

नए साल में फास्ट टैग रजर्स को बड़ी राहत...

राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHA) ने 1 फरवरी 2026 से नए FASTag के लिए अनिवार्य KYV प्रक्रिया समाप्त करने का निर्णय लिया है। यह कदम कार, जीप और वैन चालकों को राहत देगा, जिससे एक्टिवेशन के बाद होने वाली परेशानी कम होगी। मौजूदा FASTag पर भी अब नियमित KYV की आवश्यकता नहीं होगी, सिवाय कुछ विशेष मामलों के। NHA ने VAHAN पोर्टल के माध्यम से प्री-एक्टिवेशन सत्यापन को मजबूत किया है, जिससे FASTag प्रणाली अधिक सरल और पारदर्शी बनेगी।

परिवहन विशेष न्यून

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHA) ने आम वाहन चालकों को बड़ी राहत देते हुए कार, जीप और वैन के लिए जारी किए जाने वाले नए FASTag पर लागू अनिवार्य Know Your Vehicle (KYV) प्रक्रिया को 1 फरवरी 2026 से समाप्त करने का फैसला किया है। इस निर्णय का उद्देश्य FASTag एक्टिवेशन के बाद वाहन चालकों को होने वाली परेशानी और अनावश्यक उत्पीड़न को खत्म करना है। एनएचएआई के अनुसार, यदि FASTag से जुड़ी कोई लाखां लोगों को राहत मिलेगी, जिन्हें वैध

वाहन दस्तावेज होने के बावजूद FASTag जारी होने के बाद KYV प्रक्रिया के कारण देरी और असुविधा का सामना करना पड़ रहा था।

प्राधिकरण ने स्पष्ट किया कि पहले से कारों के लिए जारी किए गए FASTag पर भी अब नियमित रूप से KYV करना अनिवार्य नहीं होगा। हालांकि, कुछ विशेष मामलों में ही KYV की जरूरत पड़ेगी। इनमें FASTag के डीले होने, गलत तरीके से जारी होने या दुरुपयोग से संबंधित शिकायतें शामिल हैं। एनएचएआई के अनुसार, यदि FASTag से जुड़ी कोई शिकायत प्राप्त नहीं होती है, तो मौजूदा कार

FASTag पर KYV प्रक्रिया लागू नहीं की जाएगी। इसके साथ ही, एनएचएआई ने FASTag जारी करने वाली बैंकों के लिए प्री-एक्टिवेशन वैलिडेशन प्रक्रिया को और मजबूत किया है।

अब FASTag को सक्रिय करने से पहले VAHAN पोर्टल के माध्यम से वाहन का अनिवार्य सत्यापन किया जाएगा, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को रोका जा सके। एनएचएआई का कहना है कि यह कदम FASTag प्रणाली को अधिक सरल, पारदर्शी और उपयोगकर्ता-अनुकूल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण सुधार है।

टैपल आफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर अलाइड ट्रस्ट पंजीकृत

<https://tolwa.com/about.html> | tolwaindia@gmail.com, tolwadelhi@gmail.com



पिकी कुंडू

मंगलवार, 30 दिसम्बर 2025 को श्री मधुप तिवारी, आईपीएस, विशेष पुलिस आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था जोन II, दिल्ली पुलिस) ने दिल्ली पुलिस के प्रमुख कार्यक्रम "ऑपरेशन विश्वास" के दौरान मीडिया को संबोधित किया। इस कार्यक्रम में खोए और चोरी हुए मोबाइल फोन उनके वास्तविक मालिकों को वापस सौंपे गए।

उन्होंने जोर देकर कहा कि साइबर अपराध लगातार बदल रहा है और नागरिकों को नए तरीकों से अवगत कराने के लिए नियमित जागरूकता अभियानों की आवश्यकता है। संदेश स्पष्ट है: नागरिकों को नए साइबर अपराध रूझानों और नवीनतम तकनीकों से अवगत कराना चाहिए ताकि वे स्वयं को सुरक्षित रख सकें।

जैसे CEIR.GOV.IN पोर्टल ने खोए और चोरी हुए मोबाइल फोन खोजने का तरीका बदल दिया है, वैसे ही www.sancharsaathi.gov.in साइबर धोखाधड़ी

आज का साइबर सुरक्षा विचार : साइबर अपराध रुझानों और नवीनतम तकनीकों से अवगत रहना / कराना चाहिए ताकि वे स्वयं को सुरक्षित रख सकें

रिपोर्टिंग में एक मील का पत्थर साबित होगा। Sanchar Saathi के माध्यम से Financial Fraud Risk Indicator (FRI) का उपयोग एक सच्चा गेमचेंजर बन सकता है।

FRI की शक्ति का उपयोग
नए वर्ष की शुरुआत में हमें FRI की परिवर्तनकारी शक्ति को पहचानना होगा — यह साइबर धोखाधड़ी के विरुद्ध एक निर्णायक हथियार है।
• नागरिक www.sancharsaathi.gov.in के माध्यम से FRI से जुड़ सकते हैं।
• 22 मई 2025 को शुरू होने के बाद, केवल छह महीनों में FRI ने ₹660 करोड़ की साइबर धोखाधड़ी हानि को रोका है।
• सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, निजी बैंक, सहकारी बैंक, TPAPs और अन्य वित्तीय संस्थानों ने रिपोर्ट किया है कि संदिग्ध लेनदेन को FRI के माध्यम से Digital Intelligence Platform (DIP) पर या तो अस्वीकार कर दिया गया या चेतावनी जारी की गई।

Financial Fraud Risk Indicator (FRI) के बारे में
• FRI एक जोखिम आधारित मीट्रिक है जो संदिग्ध मोबाइल नंबरों को मध्यम, उच्च या अत्यधिक उच्च जोखिम श्रेणी में वर्गीकृत करता है।
• यह कई हितधारकों से प्राप्त इनपुट पर आधारित है:
o NCRP (राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल, I4C)
o DoT का चक्रु प्लेटफॉर्म
• बैंक, वित्तीय संस्थान और दूरसंचार सेवा प्रदाता (TSPs)
• यह बैंकों, NBFCs और UPI सेवा प्रदाताओं को अतिरिक्त सुरक्षा उपाय अपनाने में सक्षम बनाता है जब कोई मोबाइल नंबर संदिग्ध पाया जाता है।
Sanchar Saathi पहल के बारे में
Sanchar Saathi दूरसंचार विभाग (DoT) की नागरिक केंद्रित पहल है, जिसका उद्देश्य मोबाइल ग्राहकों को सशक्त बनाना, सुरक्षा को मजबूत करना और

जागरूकता फैलाना है। यह मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल दोनों रूपों में उपलब्ध है। इसकी प्रमुख सेवाएँ हैं:
• चक्रु — संदिग्ध कॉल/एसएमएस तुरंत रिपोर्ट करें।
• अपने मोबाइल कनेक्शन जानें — अनधिकृत नंबरों की पहचान और हटाएँ।
• खोए/चोरी हुए उपकरण ब्लॉक करें — मोबाइल को जल्दी ट्रेस और रिकवर करें।
• हैंडसेट की वास्तविकता जाँचें — खरीद से पहले असली/नकली की पुष्टि करें।
• विश्वसनीय संपर्क विवरण — बैंकों और वित्तीय संस्थानों के सत्यापित संपर्क देखें।
Sanchar Saathi ऐप डाउनलोड करें:
• Android
• iOS
Digital Intelligence Platform (DIP) के बारे में
Digital Intelligence Platform (DIP) DoT द्वारा विकसित एक सुरक्षित ऑनलाइन प्रणाली है, जो दूरसंचार

संसाधनों के दुरुपयोग से संबंधित जानकारी को विभिन्न हितधारकों के बीच साझा करती है। यह 1050+ संगठनों को जोड़ता है, जिनमें शामिल हैं:
• केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियाँ
• 36 राज्य/केंद्र शासित प्रदेश पुलिस बल
• I4C, GSTN, UIDAI, CBDT, PFMS, MORTH
• बैंक, वित्तीय संस्थान, TSPs
• सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे WhatsApp संकल्प
नए वर्ष 2026 का स्वागत करते हुए, आइए संकल्प लें:
• Sanchar Saathi के माध्यम से FRI को व्यापक रूप से अपनाएँ।
• बदलते साइबर खतरों के प्रति सतर्क रहें।
• नागरिकों को जागरूक करें और डिजिटल सुरक्षा उपकरणों का सक्रिय उपयोग करें।
मिलकर हम FRI को एक राष्ट्रीय सफलता की कहानी बना सकते हैं और लाखों नागरिकों को वित्तीय धोखाधड़ी से बचा सकते हैं।

एक राष्ट्रीय जनसंदेश : "जनकल्याण परिवहन सीरीज" के पाँचों भागों का जनहित - जनकल्याण — जनसूचना दृष्टिकोण से सामूहिक निष्कर्ष

जनकल्याण परिवहन सीरीज: राष्ट्र की सड़कों पर जनस्वास्थ्य की आवाज — निष्कर्ष व अर्थ

(लेखक: संजय कुमार बाठला)

परिवहन विशेष, हिंदी दैनिक (आरएनआई मान्यता प्राप्त)

*प्रस्तावना: सड़कें राष्ट्र का दर्पण हैं, भारत की सड़कें केवल यातायात की धमनियाँ नहीं, बल्कि राष्ट्र की नीतियों, नागरिकता और चेतना का प्रतिबिंब हैं।

मोटर वाहन, प्रदूषण नियंत्रण, ईंधन की गुणवत्ता या सड़क सुरक्षा — ये सब मुझे अलग-अलग नहीं, बल्कि जनजीवन का एक सतत प्रवाह हैं।

"जनकल्याण परिवहन सीरीज" इसी प्रवाह की पड़ताल करती है — वहाँ जहाँ सुविधा और जीवन, गति और स्वास्थ्य, कानून और नैतिकता एक साथ खड़े होते हैं।

भाग - दर - भाग जनहित
अर्थभाग 1 — मिलावट का ट्रैफिक: भोजन से ईंधन तक विष का सफर यह भाग केवल रासायनिक नहीं, बल्कि नैतिक चेतावनी है। जिस तरह खाने में मिलावट शरीर को बीमार करती है, वैसे ही ईंधन में मिलावट राष्ट्र की गति को प्रदूषित करती है।

जनसूचना संदेश: ईंधन गुणवत्ता की जाँच करना और रिपोर्ट करना नागरिक अधिकार और जनहित कर्तव्य दोनों हैं।
भाग 2 — धुआँ और साँस: वाहन प्रदूषण का सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट यह कड़ी हमें याद दिलाती है कि हर ईंधन की चिमनी, हर एंजॉस्ट पाइप से उठता धुआँ हमारी साँस में प्रवेश करता है। वाहन केवल सवारी नहीं, बल्कि वायु की गुणवत्ता का निर्धारक हैं।

जनकल्याण संदेश: स्वच्छ ईंधन, EV नीति और साइबा सफर को अपनाना स्वास्थ्य सुरक्षा का विस्तार है।
भाग 3 — सड़कें या राणभूमि: सुरक्षा में लापरवाही की कीमत तीसरा भाग हमें आँकड़ों और अंतरात्मा दोनों से झकझोरता है — 1.75 लाख सड़क मौतें केवल दुर्घटनाएँ नहीं, यह प्रशासनिक शिथिलता और सामाजिक असंवेदनशीलता की कीमत हैं।
जनहित चेतावनी: एक हेलमेट, एक बेल्ट या एक सिग्नल पर रुकना — हर जीवन बचाने की संभावना है। सड़क सुरक्षा कानूनी आदेश नहीं, नैतिक आदेश है।

भाग 4 — परिवहन और जनस्वास्थ्य: हर साँस की कीमत यह हिस्सा परिवहन और सार्वजनिक स्वास्थ्य की एक मजबूत कड़ी बनाता है। प्रदूषित हवा अब "पर्यावरण" नहीं, बल्कि "चिकित्सकीय



सुरक्षा में लापरवाही की कीमत
मुख्य विचार:

भोजन ही नहीं, बल्कि ईंधन और ऑटोमोबाइल उद्योग में भी मिलावट की प्रवृत्ति खतरनाक रूप से बढ़ रही है। नकली या निम्न-गुणवत्ता वाले पेट्रोल, डीजल और ल्यूब्रिकेंट्स न केवल इंजन को नुकसान पहुँचाते हैं, बल्कि वातावरण में जहरीले प्रदूषक छोड़ते हैं।

संदेश:
ईंधन गुणवत्ता नियंत्रण, BIS मानक, और निरीक्षण प्रणाली की सख्ती ही मिलावट की जड़ों पर प्रहार करेगी।

भाग 2: धुआँ और साँस — वाहन प्रदूषण से बढ़ता सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट
मुख्य विचार:

दिल्ली सहित भारत के प्रमुख शहरों में वाहन प्रदूषण फेफड़ों, हृदय और मस्तिष्क संबंधी बीमारियों का सबसे बड़ा कारण बनता जा रहा है।

संदेश:
स्वच्छ ईंधन नीति, इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन, और सार्वजनिक परिवहन की मजबूती जनस्वास्थ्य की बुनियाद है। नागरिक का जिम्मेदार व्यवहार — जैसे नियमित वाहन जाँच और साइबा सफर — भी बदलाव ला सकता है।

भाग 3: सड़कें या राणभूमि —

माना जाए। "क्लीन ट्रांसपोर्ट, हेल्दी सिटीज" अब केवल नारा नहीं, राष्ट्रीय जननीति बने।

भाग 5: नैतिकता की गाड़ी — नागरिक ही असली चालक
मुख्य विचार:

कानून और नीतियाँ अपनी जगह हैं, पर नैतिकता और जिम्मेदारी ही बदलाव का इंजन हैं। नागरिक व्यवहार में ईमानदारी, दूसरों की सुरक्षा का सम्मान और जिम्मेदार उपभोग ही मिलावट-मुक्त भारत का रास्ता दिखाएँगे।

संदेश:
सच्ची देशभक्ति वही है, जो अपने कर्तव्य से राष्ट्र और मानवता — दोनों की रक्षा करे।

(श्रृंखला निष्कर्ष): परिवहन केवल गति नहीं, बल्कि जनजीवन की धड़कन है। यदि इस धड़कन में ईंधन, वायु, और नैतिकता की शुद्धता बनी रहे — तो राष्ट्र का शरीर स्वस्थ और आत्मा सशक्त रहेगी। यही सच्चा "परिवहन में जनकल्याण" होगा।



भारत चलता है — जिम्मेदारी के पहिए पर श्रृंखला समापन

* सड़कें राष्ट्र का दर्पण, नागरिक उसका चालक।
* मिलावट-मुक्त ईंधन, शुद्ध हवा, सुरक्षित सफर — यही जनकल्याण परिवहन का मंत्र।
* पाँच भागों का सामूहिक जनसंदेश
* "नीति + नैतिकता = स्वस्थ राष्ट्र"
मिलावट, प्रदूषण, दुर्घटनाएँ, स्वास्थ्य संकट और नागरिक जिम्मेदारी — ये पाँचों कड़ियाँ एक सत्य की ओर इशारा करती हैं: परिवहन केवल मशीनरी नहीं, जीवनधारा है।
भाग - दर - भाग जनहित निष्कर्ष सीरीज का केंद्रीय अर्थ परिवहन व्यवस्था तब सफल होती है
* जब वह गति के साथ सुरक्षा,
* सुविधा के साथ शुद्धता, और
* नीति के साथ नैतिकता जोड़ती है।
यह श्रृंखला केवल विश्लेषण नहीं — जनजागरण का आह्वान है।
अंतिम जनसंदेश
* जब हर पेट्रोल पंप शुद्ध बने,
* हर वाहन PUC पास करे,
* हर सड़क सुरक्षित हो, और
* हर नागरिक जिम्मेदार — तब भारत केवल नहीं चलेगा, सजगता से उन्नत होगा।
"परिवहन में जनकल्याण" अब नारा नहीं — राष्ट्रीय संकल्प है।

आपदा" का स्वरूप ले चुकी है।
जनकल्याण संदेश: परिवहन नीति को स्वास्थ्य नीति से जोड़ना आवश्यक है — क्योंकि "क्लीन ट्रांसपोर्ट" ही "हेल्दी नेशन" की आधारशिला है।
भाग 5 — नैतिकता की गाड़ी: नागरिक ही असली चालक श्रृंखला की अंतिम कड़ी यह स्पष्ट करती है कि कोई भी नीति, चाहे कितनी भी सशक्त क्यों न हो, तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक नागरिक उसे आत्म-संस्कृति में न बदलें।
जनहित दृष्टिकोण: हर नागरिक का आचरण ही पिछले चार भागों का निष्कर्ष है — कानून अनुपालन, ईंधन शुद्धता, सुरक्षा और पर्यावरण — सबका आरंभ और अंत नैतिकता से होता है।
सीरीज का केंद्रीय अर्थ: परिवहन एक जीवनधारा है, मशीन नहीं "जनकल्याण परिवहन सीरीज" बताती है कि परिवहन

केवल वाहन व्यवस्था नहीं — यह जीवन व्यवस्था है।
* जब पेट्रोल में मिलावट रुकती है, जब वाहन स्वच्छ ईंधन से चलते हैं, जब सड़कें सुरक्षित होती हैं, तब एक राष्ट्र केवल आगे नहीं बढ़ता — वह विकसित होता है।
* परिवहन वही है जो गति के साथ भावना लाए, नीति के साथ नैतिकता जोड़े, और सुविधा के साथ सुरक्षा सुनिश्चित करे। यही सच्चा "जनकल्याण परिवहन मॉडल" है, जहाँ नागरिक, सरकार और समाज — तीनों एक ही दिशा में चलते हैं।
* निष्कर्ष: जब सड़कें सुरक्षित हों, हवा शुद्ध हो और आचरण ईमानदार — तब ही हम कह पाएँगे कि भारत चलता नहीं, सजगता से बढ़ता है।
जनकल्याण परिवहन सीरीज: राष्ट्र की सड़कों पर जनस्वास्थ्य की आवाज — समापन विशेषांक

स्वास्थ्य विशेष

स्वास्थ्य आपका कोशिश हमारी

माइग्रेन में ब्राह्मी का देसी उपाय (पुराना, आजमाया हुआ घरेलू नुस्खा)

पिकी कुट्टू
अगर आपको बार-बार माइग्रेन का दर्द कमर दर्द, थकान या कमजोरी महसूस होती है, तो अजवाइन और गुड़ का छोटा सा नुस्खा बहुत लाभकारी हो सकता है। यह नुस्खा आयुर्वेद में काफी पुराना और असरदार माना जाता है।
1. कमर दर्द में राहत देता है अजवाइन में मौजूद प्राकृतिक दर्द-निवारक तत्व * नसों को आराम देते हैं * जकड़न और सूजन कम करते हैं गुड़ शरीर को गर्मी और ताकत देता है, जिससे दर्द धीरे-धीरे कम होता है।
2. कमजोरी और थकान दूर करता है



माइग्रेन में ब्राह्मी का देसी उपाय

अजवाइन + गुड़ खाने के फायदे (कमर दर्द में आराम)

अगर महिलाओं को बार-बार कमर दर्द, थकान या कमजोरी महसूस होती है, तो अजवाइन और गुड़ का छोटा सा नुस्खा बहुत लाभकारी हो सकता है। यह नुस्खा आयुर्वेद में काफी पुराना और असरदार माना जाता है।
1. कमर दर्द में राहत देता है अजवाइन में मौजूद प्राकृतिक दर्द-निवारक तत्व * नसों को आराम देते हैं * जकड़न और सूजन कम करते हैं गुड़ शरीर को गर्मी और ताकत देता है, जिससे दर्द धीरे-धीरे कम होता है।
2. कमजोरी और थकान दूर करता है

गुड़ और अजवाइन खाने के फायदे
* → कमर दर्द
* → थकान
* → थकावट
जैसी समस्याएँ होती हैं, जिन्हें अजवाइन - गुड़ नियमित लेने से राहत मिल सकती है।
4. पाचन और गैस की समस्या ठीक करता है
* अजवाइन
* → गैस
* → अपच
* → पेट दर्द
को कम करती है, जिससे पेट से जुड़ा दबाव कम पर नहीं पड़ता।
कैसे खाएँ? (Method)
* रात को सोने से पहले
* 1/2 चम्मच अजवाइन
* गुड़ का छोटा टुकड़ा अच्छी तरह चबा कर खाएँ और उसके बाद गुनगुना दूध पी लें।

पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम (PCOS)

PCOS क्या है? पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम (PCOS) एक जटिल हार्मोनल एवं चयापचय (Metabolic) विकार है, जो मुख्यतः प्रजनन आयु में अंडाशय (ओवरी) वाले व्यक्तियों को प्रभावित करता है। यह इस समूह में पाए जाने वाले सबसे सामान्य एंडोक्राइन विकारों में से एक है और विश्व-भर में लगभग 15% प्रजनन आयु की महिलाओं को प्रभावित करता है।
विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार—PCOS किसी एक कारण से होने वाली बीमारी नहीं है, बल्कि एक सिंड्रोम है; अर्थात् लक्षणों और जैविक परिवर्तनों का ऐसा समूह, जो प्रत्येक व्यक्ति में अलग-अलग रूप और तीव्रता के साथ प्रकट हो सकता है।
अंतर्निहित जैविकी:
* पैथोफिजियोलॉजी PCOS प्रजनन एवं चयापचय प्रणालियों के हार्मोनल नियंत्रण में गड़बड़ी के कारण उत्पन्न होता है:
1. हार्मोनल असंतुलन मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस और पीयूरीटरी ग्रंथि से निकलने वाले संकेत (GnRH, LH, FSH) अंडाशय के कार्य को नियंत्रित करते हैं।
* PCOS में LH की तरंगों की आवृत्ति और तीव्रता बढ़ जाती है, जिससे अंडाशयों द्वारा एंडोजन (पुरुष-सदृश हार्मोन) का उत्पादन अधिक होने लगता है।
2. एंडोजन की अधिकता (हाइपरएंड्रोजेनिज्म) टेस्टोस्टेरोन जैसे एंडोजनों का बढ़ा हुआ स्तर PCOS की प्रमुख पहचान है।
3. इसके परिणामस्वरूप हिस्ट्रिज्म (चेहरे/शरीर पर अधिक बाल), मुंहासे तथा सिर के बालों का पतला होना (एलोपेसिया) दिखाई देता है।
4. इंसुलिन प्रतिरोध PCOS वाले अनेक लोगों में इंसुलिन रेंजिस्टेंस विकसित हो जाता है, जिसमें रक्त शर्करा नियंत्रित करने के लिए शरीर को अधिक इंसुलिन चाहिए।
* बढ़ा हुआ इंसुलिन स्तर अंडाशयों को और अधिक एंडोजन बनाने के लिए प्रेरित करता है, जिससे हार्मोनल असंतुलन और गहराता है।
5. अंडाशयों फॉलिकल का विकास अल्ट्रासाउंड में दिखने वाली "सिस्ट" वास्तव में अपरिपक्व फॉलिकल्स होती हैं, जो ओव्यूलेशन बाधित होने के कारण जमा हो जाती हैं— ये हानिकारक सिस्ट नहीं होतीं।
6. प्रणालीगत प्रभाव PCOS में हल्की लेकिन दीर्घकालिक सूजन और चयापचय परिवर्तन शामिल होते हैं। यही कारण है कि इसे अब केवल प्रजनन विकार नहीं, बल्कि एक सिस्टमिक सिंड्रोम माना जाता है।
(PubMed के अनुसार)
लक्षण एवं नैदानिक विशेषताएँ लक्षण व्यक्ति-दर-व्यक्ति भिन्न हो सकते हैं, पर सामान्यतः इनमें शामिल हैं:
* अनियमित मासिक धर्म या माहवारी का न होना
* हिस्ट्रिज्म (चेहरे/शरीर पर अधिक बाल)
* मुंहासे और तैलीय त्वचा
* सिर के बालों का पतला होना
* वजन बढ़ना या वजन घटाने में कठिनाई

भूमिका निभा सकते हैं, जिससे नए उपचार लक्ष्य सामने आ सकते हैं।
(PubMed के अनुसार)
संरचनात्मक एवं मस्कुलोस्केलेटल शोध हालिया छोटे अध्ययनों में PCOS और पोश्चर परिवर्तन (जैसे एंटीरिपर पल्सिकटिल्ट) के बीच संभावित संबंध का संकेत मिला है—संभवतः हार्मोनल और चयापचय प्रभावों के कारण—हालाँकि और शोध आवश्यक है।
(Marie Claire UK के अनुसार)
प्रबंधन एवं उपचार विकल्प हालाँकि PCOS का कोई स्थायी इलाज नहीं है, फिर भी प्रभावी रणनीतियाँ उपलब्ध हैं:
1. जीवनशैली में सुधार
* संतुलित आहार और पोषण
* नियमित शारीरिक गतिविधि एवं वजन प्रबंधन
* तनाव नियंत्रण और पर्याप्त नींद
* ये उपचार लक्षणों और चयापचय परिणामों में सुधार की आधारशिला हैं।
2. दवाएँ
* मेटफॉर्मिन— इंसुलिन रेंजिस्टेंस के लिए
* ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स— चक्र नियमित करने और एंडोजन प्रभाव घटाने हेतु
* एंटी-एंड्रोजेन्स (जैसे स्पाइरोनोलेक्टोन) — गंभीर हिस्ट्रिज्म/एकने में
* लेट्रोजोल— बांझपन में ओव्यूलेशन प्रेरण हेतु तेजी से अपनाया जा रहा है।
(JAMA Network के अनुसार)
3. प्रजनन उपचार
* ओव्यूलेशन इंडक्शन दवाएँ सहायक प्रजनन तकनीकें (जैसे IVF)
PCOS-विशिष्ट उन्नत IVF प्रोटोकॉल परिणामों को बेहतर और जोखिमों को कम करने हेतु विकसित किए जा रहे हैं।
(New York Post के अनुसार)
4. सप्लीमेंट्स एवं सहायक उपाय
इन्वॉल्यूटिंस (विशेषकर मायो-इन्वॉल्यूटिंस) इंसुलिन संवेदनशीलता और ओव्यूलेशन में सुधार के लिए चर्चा में हैं, हालाँकि गर्भावस्था परिणामों पर प्रभाव अभी अध्ययनाधीन है।
(New York Post)
जीवन-गुणवत्ता पर व्यापक प्रभाव PCOS केवल शारीरिक स्वास्थ्य को ही नहीं, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। प्राभावित व्यक्तियों में चिंता, अवसाद, शरीर-छवि से जुड़ा तनाव और मानसिक दबाव की दरें अधिक पाई जाती हैं।
(The Week के अनुसार)
सारांश: 2025 में PCOS संक्षेप में— PCOS एक बहु-कारक हार्मोनल एवं चयापचय सिंड्रोम है, जिसके लक्षण विविध होते हैं।
* निदान में अब नए बायोमार्कर और AI-आधारित उपकरण शामिल हो रहे हैं।
* GLP-1 जैसी नई दवाएँ आशाजनक हैं, पर विशिष्ट परीक्षणों की आवश्यकता है।

नए साल में इन 'आदतों' को शामिल करें, बीमारियाँ दूर भागेंगी

नया साल शुरू हो गया है, नया साल 2026 सभी के लिए उम्मीद की किरण लेकर आता है। नए साल के मौके पर लोग अपनी जिंदगी बदलने के लिए कई रेजोल्यूशन लेते हैं। ऐसे में, आज आइए कुछ ऐसी आदतों के बारे में जानें, जो आपको नए साल में हेल्दी रहने में मदद करेंगी। अगर आप भी आने वाले साल में हेल्दी रहने के लिए अपनी कुछ आदतें बदलना चाहते हैं, तो इसे जरूर पढ़ें।
आइए जानें हेल्दी रहने के लिए आप कौन सी आदतें बदल सकते हैं....
समय पर सोएं...
आजकल लोगों के सोने और खाने का समय पूरी तरह बदल गया है। बहुत से लोग रात में देर से खाते हैं और बहुत देर से सोते हैं। ऐसे में यह बीमारियों का एक बड़ा कारण भी बन सकता है। इसलिए सबसे पहले, सभी काम समय पर करने की आदत डालें। जल्दी खाएं और जल्दी सोएं। कम से कम 8 घंटे की नींद लें।
स्ट्रेस मैनेज करें...
आजकल हर कोई किसी न किसी वजह से परेशान या स्ट्रेस में रहता है। लेकिन कुछ लोगों को बहुत ज्यादा



चिंता करने की आदत होती है। इससे मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए, अपने स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए आपको मेंडिटेशन और माइंडफुलनेस जैसी स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्नीक अपनानी चाहिए।
एक्सरसाइज करें...
फिजिकली फिट रहने के लिए शरीर को एक्टिव रखना बहुत जरूरी है। इसके लिए आपको रोजाना एक्सरसाइज करने की आदत डालनी

चाहिए। इसके लिए आप मॉर्निंग वॉक, एक्सरसाइज, योगा या डांस क्लास जैसी एक्टिविटी कर सकते हैं। एक्सरसाइज से शरीर और मन दोनों फिट रहते हैं।
खाने की अच्छी आदतें...
आजकल बच्चे ही या जवान, सभी को जंक फूड और पैकड फूड खाना बहुत पसंद होता है। लेकिन यह हमारी सेहत के लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए, इस नए साल से घर का बना खाना और हेल्दी खाना खाने की आदत डालें।
पढ़ना...
पढ़ना सबसे अच्छी हॉबी है। दिन में कुछ समय कुछ अच्छा पढ़ने में बिताएं। इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इसके साथ ही, अपने विचार और अगले दिन का शेड्यूल डायरी में लिखने की आदत डालें। ये अच्छी आदतें अच्छी हेल्थ बनाए रखने में मदद करती हैं।

#पहचानो जड़ी बूटी #किस बीमारी में कौनसी काम आती है #कैसे करें उपयोग #आयुर्वेद जीवन

1. अश्वगंधा
किस बीमारी में: कमजोरी, तनाव, अनिद्रा, पुरुष-शक्ति
कैसे: 1 चम्मच चूर्ण गुनगुने दूध के साथ कब: रात को सोने से पहले
2. गिलोय
किस बीमारी में: बुखार, इम्युनिटी कमजोर, डेंगू
कैसे: 10-15 ml रस या काढ़ा कब: सुबह खाली पेट
3. तुलसी
किस बीमारी में: सर्दी-खाँसी, दमा, संक्रमण
कैसे: 5-7 पत्ते चबाएँ या काढ़ा कब: सुबह खाली पेट
4. एलोवेरा
किस बीमारी में: कब्ज, त्वचा रोग, पेट की जलन
कैसे: 20 ml रस कब: सुबह खाली पेट
5. नीम
किस बीमारी में: त्वचा रोग, खून की गंदगी
कैसे: पत्तों का रस / दातून कब: सुबह
6. आंवला
किस बीमारी में: आँखों की कमजोरी, बाल झड़ना, गैस
कैसे: 1 चम्मच चूर्ण या रस कब: सुबह
7. ब्राह्मी
किस बीमारी में: याददाश्त कमजोर, तनाव
कैसे: चूर्ण दूध के साथ कब: रात
8. शतावरी
किस बीमारी में: महिलाओं की कमजोरी, हार्मोन असंतुलन
कैसे: 1 चम्मच चूर्ण दूध के साथ कब: सुबह
9. मुलेठी
किस बीमारी में: गले की खराश, खाँसी
कैसे: छोटा टुकड़ा चूसें कब: दिन में 2 बार
10. अर्जुन
किस बीमारी में: हृदय रोग, उच्च रक्तचाप
कैसे: छाल का काढ़ा कब: सुबह-शाम
11. हरड़
किस बीमारी में: कब्ज, अपच
कैसे: चूर्ण गुनगुने पानी से कब: रात
12. बहेड़ा
किस बीमारी में: खाँसी, आँख रोग
कैसे: चूर्ण कब: सुबह
13. पुनर्नवा
किस बीमारी में: सूजन, किडनी रोग
कैसे: काढ़ा कब: सुबह
14. कालमेघ
किस बीमारी में: लिवर रोग, पीलिया
कैसे: काढ़ा कब: सुबह
15. गुड़मार
किस बीमारी में: मधुमेह (डायाबिटीज)
कैसे: चूर्ण कब: सुबह-शाम
16. भृंगराज
किस बीमारी में: बाल झड़ना, सफेद बाल
कैसे: रस या तेल कब: रात
17. दाहहल्दी
किस बीमारी में: त्वचा रोग, संक्रमण
कैसे: चूर्ण पानी के साथ कब: सुबह
18. नागरमोथा
किस बीमारी में: गैस, अपच
कैसे: चूर्ण कब: भोजन बाद



19. चिरायता
किस बीमारी में: बुखार, मलेरिया
कैसे: काढ़ा कब: सुबह
20. शंखपुष्पी
किस बीमारी में: मानसिक तनाव, नींद न आना
कैसे: सिरप/चूर्ण कब: रात
महत्वपूर्ण सावधानी
गर्भवती महिलाएँ बिना वैद्य की सलाह न लें अधिक मात्रा हानिकारक हो सकती है

बाल, पेट और जोड़, तीनों परेशानियों का एक देसी जवाब - अरंडी का तेल

पिकी कुट्टू
वैज्ञानिक कारण: अरंडी के तेल में RICINOLEIC ACID होता है, जो ANTI-INFLAMMATORY गुण रखता है।
* बालों में लगाने पर यह SCALP की DRYNESS कम करता है और HAIR FOLLICLES को NOURISHMENT देता है।
* दूध के साथ थोड़ी मात्रा लेने से BOWEL MOVEMENT SMOOTH होता है, जिससे कब्ज में राहत मिल सकती है।
* जोड़ों पर हल्की मालिश करने से BLOOD CIRCULATION बेहतर होती है और STIFFNESS कम



महसूस होती है।
आयुर्वेदिक कारण:
* आयुर्वेद में अरंडी का तेल वात दोष को शांत करने वाला माना गया है।
* वात के असंतुलन से ही बाल झड़ना, कब्ज और जोड़ों का दर्द बढ़ता है।
इसलिए अरंडी का तेल तीनों समस्याओं में उपयोगी माना जाता है।
फायदे (BENEFITS):
* बालों की जड़ें मजबूत होती हैं
* कब्ज में नरमी और आराम मिलता है
* जोड़ों के दर्द में राहत
* शरीर में STIFFNESS कम होती है।

8वां वेतन आयोग लागू, केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों की सैलरी व पेंशन बढ़ी

संगिनी घोष विशेष संवाददाता परिवहन विशेष

आज से 8वां वेतन आयोग लागू हो गया है, जिससे देश भर के केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को राहत मिली है। इसके लागू होने से सैलरी, पेंशन, महंगाई भत्ता और अन्य सुविधाओं में बढ़ोतरी हुई है। इससे लाखों कर्मचारियों और रिटायर्ड लोगों को बढ़ती महंगाई से निपटने में मदद मिलेगी।

नए वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों का बेसिक वेतन और दूसरी सुविधाओं में भी बदलाव किया गया है ताकि आज के खर्चों के अनुसार फायदा मिल सके।

पेंशनरों की पेंशन और महंगाई राहत भी बढ़ाई गई है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।

8वां वेतन आयोग को लागू करने से पहले सरकार ने कर्मचारी संगठनों और विशेषज्ञों से बातचीत की थी। सरकार का मकसद कर्मचारियों को सही वेतन देना और साथ ही देश के बजट का ध्यान रखना है। खास तौर पर छोटे और मध्यम स्तर के कर्मचारियों पर ध्यान दिया गया है, ताकि वेतन का अंतर कम हो और संतोष बढ़े।

सैलरी और पेंशन बढ़ने से लोगों के पास खर्च करने के लिए ज्यादा पैसा होगा,



जिससे घर, सामान और सेवाओं पर खर्च बढ़ सकता है। इससे देश की अर्थव्यवस्था

को भी फायदा होने की उम्मीद है। हालांकि, सरकार पर खर्च का बोझ भी

बढ़ेगा, इसलिए सही योजना बनाना जरूरी होगा। सरकार ने कहा है कि जो भी बकाया राशि है, उसे तय समय पर दिया जाएगा और सभी विभागों को सही तरीके से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। ज्यादातर कर्मचारी और पेंशनर इस फैसले से खुश हैं, हालांकि कुछ छोटे मुद्दों पर आगे चर्चा हो सकती है।

कुल मिलाकर, 8वां वेतन आयोग का लागू होना एक अहम कदम है, जिससे सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों की आय बढ़ेगी और वेतन व्यवस्था को आज के समय के अनुसार बेहतर बनाया गया है।

नववर्ष: आत्ममंथन, आत्मनिर्माण से विजयध्वज तक

नव वर्ष दस्तक देता है चुपचाप, न कोई शोर, न कोई दावा, बस पूछता है हमसे इतना— क्या बदलेगा हम में वक्त का नजरिया? बीते कल को दोष न दें, वह शिक्षक था, शत्रु नहीं, हर टोकर ने गढ़ा हमें, हर हार बनी नई कहानी। नया साल कहता है— तेज नहीं, मजबूती सह चलो, ऊँचा नहीं, सार्थक बने,

जीतो नहीं, योगदान दो। जहाँ शब्द नहीं, आचरण बोले, जहाँ सत्ता नहीं, निश्चल सेवाभाव हो, जहाँ भीड़ नहीं, विवेक चले, और हर निर्णय में मानवता की मिसाल हो। नववर्ष यह भी सिखलाए— सफलता केवल अर्जित में नहीं, अर्पण करने में भी होती है, अहंकार, लालच और भय को। चलो ऐसे समाज की स्वतः नींव रखें— जहाँ भूख शर्मिदा हो जाए,



व न्याय प्रतीक्षा न करे - स्वतः मिले, और सच को सुरक्षा मिल जाए। नया वर्ष कोई परिकल्पना नहीं,

यह हमसे ही आकार लेता है, हम जैसे सोचते, बोलते, करते हैं, वही तो आने वाला कल स्वयं बनता है।

इस नववर्ष संकल्प लें— कम बोलें, अधिक करें, कम चाहें, अधिक दें, और जो हैं, उसमें ही संतोष रखें। नववर्ष आपके जीवन में समृद्धि, ऐश्वर्य, प्रेम, मानवता, स्पष्टता, साहस और विजय पताका की रोशनी लेकर आए

सीएम नायब सैनी की कैबिनेट के फैसलों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस

पिकी कुंडू

सीएम ने प्रदेशवासियों को नए साल की बधाई एवं शुभकामनाएं दी नया साल सुख समृद्धि लेकर आने की कामना करता हूँ

कैबिनेट में आज 6 एजेंडे थे सभी को मंजूरी दी गई

पंचकुला में गऊशाला के लिए भूमि पट्टे को मंजूरी कैबिनेट ने दी है

बरवाला के रतेवाली गांव में कामधेनु गौ सेवा समिति को 4 एकड़ जमीन देने की मंजूरी दी है

परिवहन विभाग में 2002 में कॉन्ट्रैक्ट पर जो ड्राइवर थे उन्हें तमाम वित्तीय लाभ देने का फैसला कैबिनेट ने किया है

इन ड्राइवर को शुरुआती तारीख से नियमित मानकर सभी लाभ दिया जाएगा— सीएम

सीएम ने कहा स्वर्गीय संदीप ASI की पत्नी संतोष को सरकारी नौकरी देने पर मंत्री मंडल ने फैसला किया है

संतोष को पीजीटी एमडीयू के कैम्पस स्कूल में नियमों के मुताबिक दी गई है— सीएम

कच्ची कॉलोनी में की जमीन ट्रांसफर करके गलत तरीके से जो रजिस्ट्री करवाई



जा रही थी वो अब नहीं होगी— सीएम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ाया गया है विशेष योजना शुरू की गई है— सीएम

सीएम ने कहा इसी को आगे बढ़ाते हुए हरियाणा में आज बेटियों के लिए शुरू की

गई योजना का विस्तार किया गया है आज इस योजना में कुछ नई श्रेणियों को जोड़ने की मंजूरी दी है इस लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ उन महिलाओं को मिलेगा जिनके बच्चों के 10 वी और 12 वीं में 80 प्रतिशत से अधिक नम्बर

ऐसी महिलाओं को भी 2100 रुपये की राशि मिलेगी— सीएम कुपोषण और एनीमिया से ग्रसित बच्चों को जिन माताओं ने बहार निकाला है उनको भी लाडो लक्ष्मी योजना का 2100 रुपये का लाभ मिलेगा

महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त

बनाने की पहल की गई है 1100 रुपए सीधे महिलाओं को मिलेगी 1000 हजार राशि सरकार डिपॉजिट करेगी जो ब्याज सहित मिलेगा— सीएम

लाभार्थी की असामयिक मृत्यु पर डिपॉजिट राशि नौमनी को तुरंत जारी की जाएगी— सीएम

दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत 10 लाख 255 महिलाओं ने आवेदन किया है

प्रदेश में 8 लाख को सहायता राशि मिल रही है बाकी की वेरिफिकेशन चल रही है

250 करोड़ की सहायता दो किस्तों में अब तक दी गई है— सीएम 2014 से पहले लिंगानुपात

चिंताजनक था इसके बाद प्रधानमंत्री ने पानीपत में 2015 से बेटे बचाओ बेटे पढ़ाओ की शुरुआत की

2025 में अब हरियाणा का लिंगानुपात 923 तक पहुंच गया है— सीएम

सीएम ने कहा PNDT एक्ट के तहत सरकार ने कड़ी कार्रवाई की है।

मंगल गान के मध्य धूमधाम से प्रारंभ हुआ प्रियावल्लभ लाल जू महाराज का त्रिदिवसीय 212 वां पाटोत्सव

महोत्सव के अंतर्गत फोगला में चल रही श्रीमद्भागवत कथा में श्रीहित ललित वल्लभ नागार्च ने प्रथम दिन श्रवण कराई महात्म्य की कथा (डॉ. गोपाल चतुर्वेदी)

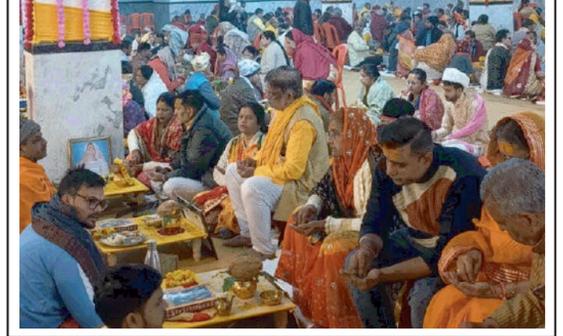
वृन्दावन छीपी गली स्थित श्रीप्रिया वल्लभ कुंज में श्रीहित उत्सव चैरिटेबल ट्रस्ट (रजि.) के द्वारा अठारहवीं शताब्दी के रससिद्ध संत, प्रख्यात वाणीकार श्रीहित परमानंद दास महाराज एवं उनकी शिष्या महारानी बखत कुंवर (प्रिया सखी) जू के सेव्य ठाकुर श्री विजय राधावल्लभ लाल व ठाकुर श्री प्रियावल्लभ लाल जू महाराज का त्रिदिवसीय 212 वां पाटोत्सव विभिन्न धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ प्रारंभ हो गया है। महोत्सव का शुभारंभ मंगल गान के मध्य श्रीराधा वल्लभीय संप्रदायचार्य गोस्वामी श्रीहित गोविंद लाल महाराज, आचार्य सुकृत लाल गोस्वामी महाराज एवं रसिक संत श्यामसुंदर दास के कर-कमलों द्वारा श्रीहित हरिवंश नामांकित ध्वजा पूजन एवं अखंड श्रीहरिनाम संकीर्तन के साथ हुआ।

मंदिर सेवायत आचार्य विष्णुमोहन नागार्च, प्रख्यात भागवताचार्य श्रीहित ललित वल्लभ नागार्च एवं आचार्य रसिक वल्लभ नागार्च ने वैदिक मंत्रोच्चार के मध्य महाराजश्री के चरण कमलों की पूजा अर्चना की इसके साथ ही श्रीराधा सुधा निधि, हित चतुर्पासी, हित सेवक वाणी आदि के मूल पाठ भी प्रारंभ हो गए हैं।

महोत्सव के अंतर्गत फोगला आश्रम में 170 श्रीमद्भागवत के मूलपाठ के साथ दिव्य श्रीमद्भागवत कथा प्रारंभ हुई जिसका शुभारंभ श्रीराधावल्लभीय संप्रदायचार्य टिकैत अधिकारी गोस्वामी मोहित मराल महाराज ने दीप प्रज्वलन करके किया। तत्पश्चात व्यास पीठ पर आसीन श्रीहित ललित वल्लभ नागार्च ने अपनी रसमयी वाणी के द्वारा देश-विदेश से आए समस्त भक्तों-श्रद्धालुओं को व्यासजी महाराज द्वारा रचित श्रीमद्भागवत महापुराण के महात्म्य की कथा का रसास्वादन कराया इससे पूर्व श्रीप्रियावल्लभ कुंज से फोगला आश्रम तक गाजे-बाजे के मध्य श्रीमद्भागवतजी की भव्य शोभायात्रा निकाली गयी जिसमें सैकड़ों महिलाएं पीत वस्त्र पहने व सिर पर मंगल कलश धारण किए साथ चल रही थी। साथ ही असंख्य भक्त-श्रद्धालु श्रीहरिनाम संकीर्तन करते हुए शामिल हुए।

रात्रि को प्रख्यात भजन गायक मुकुल द्विवेदी के द्वारा संगीतमय श्रीराधा नाम संकीर्तन की भावमयी प्रस्तुति दी गई।

इस अवसर पर प्रख्यात साहित्यकार रूपायि रत्नर डॉक्टर गोपाल चतुर्वेदी, संत प्रवर रामदास महाराज (अयोध्या), भाजपा नेत्री श्रीमती पिकी कुंडू, महोत्सव के मुख्य यजमान श्रीमती सिंधु-मुकेश गोयल (रायपुर, छत्तीसगढ़), श्रीमती अनिता-कमल अग्रवाल, श्रीमती कौशल-अमिताभ अग्रवाल, श्रीमती मिताली-दीपक अग्रवाल, श्रीमती कृष्णा-कैलाश अग्रवाल, श्रीमती निशा-अंकित अग्रवाल, तरुण मिश्रा, भरत शर्मा, हितवल्लभ नागार्च आदि के अलावा विभिन्न क्षेत्रों के तमाम गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।



आधुनिक डिजिटल युग में संवैधानिक, लोकतांत्रिक नागरिकता व युवा भारत के दृष्टिकोण में, मनमुख, गुरुमुख व सनमुख स्वभाव-एक समग्र अंतरराष्ट्रीय विश्लेषण

लोकतांत्रिक देश में जब नागरिक मनमुख स्वभाव से संचालित होते हैं, तो लोकतंत्र अधिकारों की भीड़ बन जाता है, परंतु जब वे गुरुमुख व सनमुख होते हैं, तो लोकतंत्र लोक-कल्याण का जीवंत तंत्र बनता है— एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र

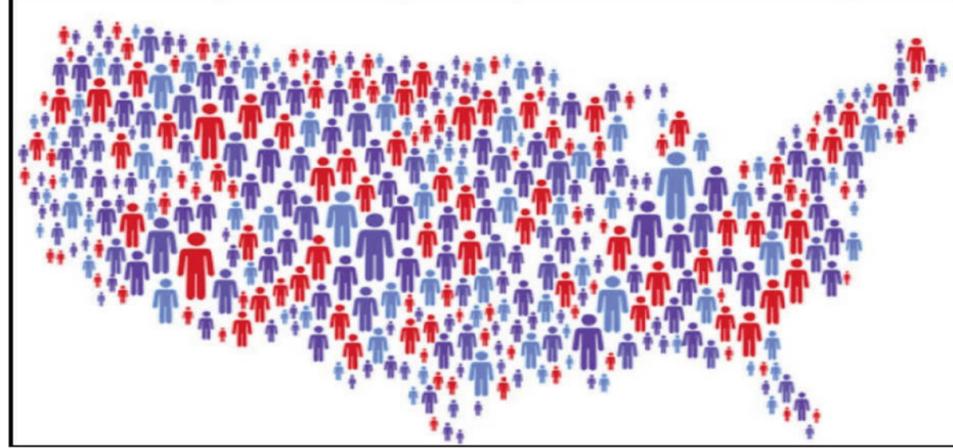
गोंदिया - वैश्विक स्तर पर मनुष्य का जीवन केवल उसकी शिक्षा, धन या पद से नहीं, बल्कि उसके स्वभाव से संचालित होता है। इतिहास गवाह है कि जिन व्यक्तियों, समाजों और राष्ट्रों ने अपने स्वभाव को अनुशासन, नैतिकता और उच्च मूल्यों से जोड़ा, वे दीर्घकालीन सफलता के प्रतीक बने। भारतीय दर्शन में मानव स्वभाव को समझाने के लिए मनमुख, गुरुमुख और सनमुख जैसे गहन और सांस्कृतिक सिद्धांत दिए गए हैं। ये अवधारणाएँ केवल धार्मिक नहीं, बल्कि वैश्विक मानव व्यवहार विज्ञान की भी कसीटी पर खरी उतरती हैं। आज जब विश्व नेतृत्व संकट, नैतिक पतन, मानसिक तनाव और मूल्य-संक्रमण से गुजर रहा है, तब इन स्वभावों का विश्लेषण अंतरराष्ट्रीय स्तर पर और भी प्रासंगिक हो जाता है। मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र यह मानता हूँ कि किसी भी लोकतंत्र को सफलता केवल उसके संविधान की सुंदर भाषा या संस्थाओं की मजबूती से तय नहीं होती, बल्कि इस बात से तय होती है कि उसके नागरिकों का स्वभाव कैसा है। संविधान नागरिकों को अधिकार देता है, परंतु यह अपेक्षा भी करता है कि नागरिक विवेकशील, उत्तरदायी और नैतिक होंगे। जब नागरिक मनमुख स्वभाव से संचालित होते हैं, तो लोकतंत्र अधिकारों की भीड़ बन जाता है; और जब वे गुरुमुख व सनमुख होते हैं, तो लोकतंत्र लोक-कल्याण का जीवंत तंत्र बनता है।

साथियों बात अगर हम मनमुख से गुरुमुख सनमुख की यात्रा को संविधान, लोकतंत्र और नागरिकता के संदर्भ में समझने की करें तो (1) मनमुख स्वभाव और लोकतंत्र का क्षरण-मनमुख नागरिक वह है जो संविधान को केवल अपने हित के औजार की तरह देखता है। उसे अधिकार याद रहते हैं, कर्तव्य नहीं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो

लोकतंत्रों में बढ़ता ध्रुवीकरण, हिंसक असहमति, टैक्स चोरी, सार्वजनिक संपत्ति का दुरुपयोग, ये सभी मनमुख नागरिकता के लक्षण हैं। जब हमें राष्ट्र से ऊपर हो जाता है, तब संविधान की आत्मा कमजोर पड़ती है। (2) गुरुमुख नागरिकता- संवैधानिक विवेक की नींव गुरुमुख नागरिक संविधान को अपना नैतिक गुरु मानता है। वह कानून के शब्दों के साथ-साथ उसके उद्देश्य को भी समझता है, न्याय, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। ऐसा नागरिक मतदान को केवल अधिकार नहीं, बल्कि जिम्मेदारी मानता है। विश्व के सफल लोकतंत्रों में नागरिकों का यही गुरुमुख स्वभाव संस्थाओं को मजबूत बनाता है। (3) सनमुख लोकतंत्र: अधिकार से आगे मानवता सनमुख नागरिकता लोकतंत्र को केवल राष्ट्र तक सीमित नहीं रखती, बल्कि उसे वैश्विक मानवता से जोड़ती है। पर्यावरण संरक्षण, अल्पसंख्यक अधिकार, शरणार्थी संवेदनशीलता ये सब सनमुख दृष्टि के बिना संभव नहीं। यही दृष्टि संविधान को मानव गरिमा का वैश्विक दस्तावेज बनाती है। इसलिए हम कर सकते हैं कि यदि नागरिक मनमुख रहे, तो संविधान केवल किताब बनेगा; यदि नागरिक गुरुमुख बनें, तो संविधान व्यवस्था बनेगा; और यदि नागरिक सनमुख बनें, तो संविधान मानवता का पशुदंशक बनेगा।

साथियों बात अगर हम मनमुख से गुरुमुख, सनमुख की यात्रा को भारत के भविष्य युवाओं से जोड़कर समझने की करें तो, युवा ही राष्ट्र का स्वभाव हैं। आज का युवा केवल कल का नागरिक नहीं, बल्कि आज का निर्माता है। उसका स्वभाव तय करेगा कि भविष्य में राष्ट्र कैसा होगा। यदि युवा मनमुख हैं, तो तकनीक भी विनाश का औजार बनेगी; और यदि युवा गुरुमुख-सनमुख हैं, तो वही तकनीक मानवता की सेवा करेगी। (1) मनमुख युवा: तात्कालिक सफलता का भ्रम-आज का युवा यदि केवल त्वरित प्रसिद्धि, आसान पैसा और सोशल मीडिया की वाहवाही के पीछे भागता है, तो वह मनमूखता की वाहवाही को सेवा करेगा। (2) गुरुमुख युवा: तात्कालिक सफलता का भ्रम-आज का युवा यदि केवल त्वरित प्रसिद्धि, आसान पैसा और सोशल मीडिया की वाहवाही के पीछे भागता है, तो वह मनमूखता की वाहवाही को सेवा करेगा। (3) सनमुख युवा: मानसिक तनाव, अवसाद और उद्देश्यहीनता इसी का परिणाम हैं। मनमुख युवा प्रतियोगिता तो जीतना चाहता है, पर धैर्य नहीं रखना चाहता। (2) गुरुमुख

मनमुख: गुरुमुख: सनमुख



युवा: कौशल के साथ संस्कार-गुरुमुख युवा वह है जो सीखने को गुरु मानता है, शिक्षक, अनुभव, असफलता और अनुशासन को वह जानता है कि वास्तविक सफलता रातों-रात नहीं आती। विश्व के नवाचार, स्टार्ट-अप और शोध नेतृत्व इसी स्वभाव से निकले हैं। (3) सनमुख युवा: करियर से आगे योगदान-सनमुख युवा अपने करियर को समाज से जोड़ता है। वह पूछता है- मैं क्या बूँ? के साथ-साथ मैं किसके काम आऊँ? यही युवा जलवायु परिवर्तन, सामाजिक असमानता और शांति प्रयासों में नेतृत्व करता है।

साथियों बात अगर हम मनमुख से गुरुमुख, सनमुख की यात्रा को प्रशासनिक, आध्यात्मिक समन्वित स्थिति सुशासन का बाहरी अनुशासन और आत्मशासन की आंतरिक शक्ति इस रूप में समझने की करें तो, शासन की गुणवत्ता शासक के स्वभाव से ही अधिक सफल होने की संभावना रखती है, प्रशासन

केवल नियमों से नहीं, बल्कि प्रशासक के स्वभाव से चलता है। इतिहास बताता है कि जिन प्रशासक मनमुख होता है, तो नियम भी भ्रष्ट हो जाते हैं; और जब वह गुरुमुख-सनमुख होता है, तो सीमित संसाधनों में भी सुशासन संभव हो जाता है। (1) मनमुख प्रशासन- सत्ता का अहंकार-मनमुख प्रशासक पद को अधिकार समझता है, सेवा नहीं। इससे लालफीताशाही, भ्रष्टाचार और जन-अविश्वास जन्म लेता है। वैश्विक स्तर पर प्रशासनिक विफलताओं का मूल कारण यही स्वभाव है। (2) गुरुमुख प्रशासन-नियम +विवेक गुरुमुख प्रशासक नियमों को गुरु मानता है, पर विवेक से काम लेता है। वह संविधान, कानून और नैतिकता का आत्मसात करता है। ऐसे प्रशासन से नागरिकों का विश्वास बढ़ता है और संस्थाएँ सशक्त होती हैं। (3) सनमुख नेतृत्व- सत्ता से सेवा तक- सनमुख प्रशासक सत्ता को साधना मानता है। वह निर्णय लेते समय सबसे कमजोर व्यक्ति को ध्यान में रखता है। यही

आध्यात्मिक चेतना प्रशासन को मानवीय बनाती है, जहाँ फाइलों के पीछे चेहरे दिखते हैं। साथियों बात हम मनमुख, गुरुमुख और सनमुख स्वभाव को समझने की करें तो, (1) मनमुख स्वभाव का तात्पर्य है ऐसा व्यक्ति जो केवल अपने मन, इच्छा, वासना, अहंकार और तात्कालिक लाभ के अनुसार निर्णय लेता है। वह न तो विवेक को महत्व देता है, न ही गुरु, समाज, शास्त्र या नैतिक मूल्यों को। आधुनिक वैश्विक संस्कृति में यह स्वभाव उपभोक्तावाद भोगवाद और अति-व्यक्तिवाद के रूप में व्यापक रूप से दिखाई देता है। राजनीति और शासन में मनमुख प्रवृत्ति के दुष्परिणाम व त्रासदी भयंकर प्रमाण में होती हैं। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में जब शासक मनमुख स्वभाव से निर्णय लेते हैं, तो सत्ता अहंकार, भ्रष्टाचार और युद्ध को जन्म देती है। इतिहास में कई साम्राज्य केवल इसलिए गिरे क्योंकि उनके नेतृत्व ने जनकल्याण की बजाय व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को

चुना। यह स्वभाव राष्ट्रों को भी अस्थिर कर देता है। (2) गुरुमुख स्वभाव का अर्थ है, गुरु, विवेक, ज्ञान और नैतिक मार्गदर्शन के अनुसार जीवन जीना। यहाँ 'गुरु' केवल व्यक्ति विशेष नहीं, बल्कि सत्य, अनुभव, संविधान, नैतिकता और सामूहिक विवेक का प्रतीक है। गुरुमुख व्यक्ति अपने मन को अनुशासित करता है, न कि उसका दास बनता है। जब शासन गुरुमुख स्वभाव से चलता है, तो नैतिक-निर्माण में पारदर्शिता, जवाबदेही और न्याय प्राथमिकता बनते हैं। संविधान भी एक प्रकार का 'गुरु' है, जो सत्ता को मर्यादा में रखता है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सुशासन के सफल मॉडल इसी सिद्धांत पर आधारित हैं। (3) सनमुख स्वभाव का अर्थ है, सत्य, सद्गुण, सेवा और सार्वभौमिक मानव मूल्यों की ओर उन्मुख होना। यह स्वभाव गुरुमुख से भी आगे जाकर व्यक्ति को स्वार्थ से परमार्थ की यात्रा पर ले जाता है। यहाँ व्यक्ति केवल अपने या अपने समाज के बारे में नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता के कल्याण के बारे में सोचता है। आज जब जलवायु परिवर्तन, युद्ध, शरणार्थी संकट और असमानता जैसी वैश्विक समस्याएँ सामने हैं, तब सनमुख स्वभाव की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक है। यह स्वभाव 'वसुधैव कुटुम्बकम्' को व्यवहार में उतारता है। अंतरराष्ट्रीय मानवतावादी संगठनों चिकित्सकों शिक्षकों और स्वयंसेवकों में यह स्वभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। यही स्वभाव विश्व को अधिक मानवीय बनाता है। सनमुख स्वभाव किसी एक धर्म या परंपरा तक सीमित नहीं है। यह एक सार्वभौमिक नैतिक चेतना है, जो आधुनिक विज्ञान, तकनीक और विकास के साथ भी सामंजस्य बिठा सकती है। यह व्यक्ति को भीतर से मजबूत और बाहर से उपयोगी बनाता है। अतः अगर हम उपरोक्त पुरे विवरण का अध्ययन कर इसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि सुशासन याने बाहरी अनुशासन (कानून) आंतरिक अनुशासन याने स्वभाव, मनमुख से सत्ता बिगाड़ती है, गुरुमुख से व्यवस्था चलती है, और सनमुख से इतिहास बनता है। आओ, मनमुख स्वभाव छोड़ें। गुरुमुख बनकर विवेक अपनाएँ। सनमुख बनकर मानवता को प्राथमिकता दें। यही व्यक्तिगत सफलता, सुशासन और विश्व-कल्याण का साझा मार्ग है।

संवेदनशीलता, साफगोई और ईमानदार इंसान होना ही बड़ा कवि होने की शर्त है : विनोद कुमार शुक्ल, नासिर अहमद सिकंदर और राजा हैदरी को श्रद्धांजलि

(रिपोर्ट : पूर्णचंद्र रथ)

रायपुर। वर्ष 2025 ने जाते-जाते छत्तीसगढ़ के साहित्य जगत की ऐसी तीन कद्दावर हस्तियों को छीन लिया, जिनका स्थान हमेशा रिक्त रहेगा। 30 दिसम्बर को विनोद कुमार शुक्ल, नासिर अहमद सिकंदर और राजा हैदरी को राजधानी रायपुर के साहित्यकारों ने शिहत से याद किया। कार्यक्रम का आयोजन जनवादी लेखक संघ, जन संस्कृति मंच और इप्ता ने मिल-जुलकर किया था।

श्रद्धांजलि सभा की शुरुआत जन संस्कृति मंच के राष्ट्रीय सचिव राजकुमार सोनी के वक्तव्य से हुई। उन्होंने तीनों साहित्यकारों के योगदान को रेखांकित किया और कहा कि जानपीठ पुरस्कार से सम्मानित विनोद कुमार शुक्ल अपनी रचनाओं से विगत 6 दशकों से देश के साहित्य की मुख्यधारा में छत्तीसगढ़ का लगातार प्रतिनिधित्व कर रहे थे, तो जनवादी तेवर की कविताएं रचने वाले नासिर को बदीलत छत्तीसगढ़ के दर्जनों कवियों को राष्ट्रीय स्तर पर चिन्हांकित किया जा सका। राजा हैदरी भी अपने जाने के बाद प्रदेश की मिट्टी में खाद बन कर अच्छे रचनाकारों को प्रोत्साहित करते रहेंगे।

प्रगतिशील लेखक संघ के

जिला अध्यक्ष अरुणकांत शुक्ला ने विनोद कुमार शुक्ल को मनुष्यता के कवि और नासिर को जनवादी चेतना के कवि के रूप में याद किया। जनवादी लेखक संघ के प्रदेश अध्यक्ष परदेशी राम वर्माने नासिर अहमद के सांप्रदायिकता के खिलाफ मजबूती से खड़े होने को याद किया। उन्होंने कहा कि देश में सांप्रदायिक मनोभाव के विकास से वे काफी व्यथित थे। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और सांप्रदायिकता के खिलाफ लेखकों को एकजुट करने के काम में लगे रहे। साहित्य में प्रचलित 'कला, कला के लिए' सिद्धांत का विरोध करते हुए उन्होंने कला को जीवन की राजनीति से जोड़ने की पहलकदमी की। इस प्रकार, उनका पूरा साहित्य कलावाद की उलटबासियों और सांप्रदायिकता के खिलाफ युद्ध का घोषणापत्र है, जो साहित्य को प्रगतिशील-जनवादी राजनीति और मानवीय सरोकारों के साथ जोड़ने का काम करता है। उनके देहावसान पूरे संगठन और साहित्यिक सरकारों के लिए अपूरणीय क्षति है।

वरिष्ठ शायर मीर अली मीर साहब ने तीनों साहित्यकारों को खुशबू की उपमा देते हुए कहा कि दिसंबर में एक सप्ताह के भीतर तीन-तीन विभूतियों का जाना देश के साहित्य जगत के लिए भी बड़ी



क्षति है, जिससे उबरने में बहुत वक्त लगेगा। सुखनवर हुसैन सुखनवर ने राजा हैदरी के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि अपनी नज्मों और गजलों से हैदरी साहब ने छत्तीसगढ़ के उर्दू साहित्य में विशिष्ट पहचान बनाई थी। वे रायपुर में मरकज-ए-अदम के संस्थापक थे, आजीवन अध्यक्ष थे और श्लोक पत्रिका के संपादक-प्रकाशक थे।

जलेंस के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य डॉ. नंदन ने 2003 से विनोद कुमार शुक्ल के साथ अपने संबंधों का जिक्र करते हुए

जनवादी कवि-आलोचक नासिर अहमद सिकंदर से अपने नागार्जुन साहित्य पर शोध के दौरान बड़ी निकटता को बताया। प्रलेसं के नंद कुमार कंसारी ने विनोद कुमार शुक्ल से हर बार मिलने को अद्भुत मुलाकात बताया, तो डॉ. आलोक वर्माने उनके संपूर्ण साहित्य को पढ़ कर ही उनके बारे में कोई राय बनाने का आग्रह किया। विविध भारती के उद्घोषक रहे कमल शर्माने शुक्ल से जुड़े अपने अनुभवों का जिक्र किया।

स्थानीय दैनिक नवभारत की साहित्य संपादक आफताब बेगम

ने भी विनोद कुमार शुक्ल तथा नासिर अहमद सिकंदर के रचनात्मक योगदान का जिक्र किया।

सभा का संयोजन तथा संचालन कर रहे जलेंस के राज्य सचिव पूर्णचंद्र रथ ने तीनों विभूतियों के निष्काम योगदान और उनके सृजन की ईमानदारी का जिक्र किया। नासिर की संक्षिप्त, लेकिन प्रभावी कविताओं का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि साक्षात्कारों पर केन्द्रित श्रृंखला 'आपने सामने' के संपादन के लिए भी वे काफी चर्चित हुए थे। हाल ही में कवि

संतोष चतुर्वेदी के ब्लाग 'पहली बार' में युवा कवियों की कविताओं पर उनकी नियमित टिप्पणी भी उल्लेखनीय है। उन्होंने साहित्यिक पत्रिका 'समकालीन हस्ताक्षर' के केदारनाथ अग्रवाल तथा चन्द्रकांत देवताले पर केन्द्रित दो अंकों का संपादन भी किया था। इन अंकों के कारण पूरे देश के साहित्य जगत का ध्यान उनके संपादकीय कौशल पर गया। वे न केवल उत्कृष्ट साहित्यकार थे, बल्कि कुशल संगठनकर्ता भी थे।

श्रद्धांजलि सभा को संस्कृति कर्मी निसार अली, मिनहाज अदम, फ़जले अब्बास सैफी, सनियारा खान ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम में पत्रकार-कवि समीर दीवान, रूमा सेनगुप्ता, रेणु नंदी, सैयद सलमा, सुधा बाघ, आफताब बेगम, मो. शमीम, डॉ. विप्लव वंद्योपाध्याय, अजीज साधू, इंद्र राठौर, हरीश कोटक एवं अन्य कई रचनाकार-संस्कृति कर्मी शामिल थे।

सभी आयोजक संगठनों की ओर से जलेंस के शायर शिज्जू शकूर ने आभार व्यक्त करते हुए कहा कि अब तो दिसंबर के महीने से ही डर बढ़ जाता है। संवेदनशीलता, साफगोई और ईमानदार इंसान होना ही बड़ा कवि होने की शर्त है और विनोद कुमार शुक्ल, नासिर अहमद सिकंदर

आरएसएस नेटवर्क का खुलासा

(आलेख : सेवरा, अनुवाद : संजय पराते)

पहली बार, शोधकर्ताओं ने आरएसएस से जुड़े संगठनों के रहस्यमयी नेटवर्क की तस्वीर सामने लाने के लिए सबूत इकट्ठा किए हैं -- और नतीजा परेशान करने वाला है। उन्होंने उन 2500 संगठनों के एक नेटवर्क का पता लगाया है, जिन्हें संघ से वैचारिक, संगठनात्मक और अक्सर आर्थिक मदद मिलती है। इन 2500 संगठनों में से 2240 भारत में हैं, जबकि बाकी 39 देशों में फैले हुए हैं। उन्होंने यह भी मानचित्र बनाया है कि ये संगठन एक-दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं, जिससे मातृ संगठन आरएसएस से उनके बहुस्तरीय संबंध सामने आए हैं। सामाजिक सेवा या धार्मिक-सांस्कृतिक संगठनों के इस विशाल नेटवर्क के जरिए ही आरएसएस अपनी हिंदुत्व की जहरीली विचारधारा फैलाता है।

इस तस्वीर को एक साथ जोड़ने में छह साल लंबा समय लगा। यह काम पेरिस के एकेडमिक संस्थान सेरी-साईसेज पो और दिल्ली की मैगज़ीन ड कारवां के शोधकर्ताओं ने किया। नेटवर्क में हर संगठन के स्थान और अन्य विवरण दिखाने वाला एक परस्पर संवादात्मक मानचित्र कारवां की वेबसाइट पर उपलब्ध है। इसमें एक नेटवर्क प्रतिचित्रण (मैपिंग) भी है, जो इन संगठनों के एक-दूसरे के साथ संबंध दिखाती है। कारप्रणाली का विवरण और मुख्य लेखक फेलिक्स पाल का एक लेख भी ऑनलाइन उपलब्ध है।

मानचित्र में भारत पर ज़ूम करने पर पता चलता है कि कुनैन-किन राज्यों में आरएसएस से जुड़े ऐसे कितने संगठन हैं। ऐसे संगठनों वाले कुछ बड़े राज्य हैं: उत्तर प्रदेश - 180; महाराष्ट्र - 259; कर्नाटक - 174; गुजरात - 136; केरल - 212; मध्य प्रदेश - 73; पश्चिम बंगाल - 55; तमिलनाडु - 76। जम्मू-कश्मीर में ऐसे 75 संगठन हैं, जबकि उत्तर-पूर्व के आठ राज्यों में कुल 75 संगठन हैं, जिनमें से अकेले असम में 44 हैं। ये संख्याएँ शायद ऐतिहासिक विरासत को दिखाती हैं -- जैसे उत्तरप्रदेश या महाराष्ट्र या उत्तर-पूर्व में -- जहाँ आरएसएस दशकों से सक्रिय है, या फिर ये पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल जैसे राज्यों में हाल की प्राथमिकताओं को दिखाती हैं।

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, मोटे तौर पर कहे तो, आरएसएस का नेटवर्क पुराने और नए, दोनों तरह के प्रवासी भारतीयों के बीच फैला हुआ है। ड कारवां की शोध के अनुसार, उदाहरण के लिए, कैरिबियन या मॉरीशस या फिजी, या दक्षिण-पूर्व एशिया जैसे ऐतिहासिक प्रवासी हिंदू आबादी वाले ज़्यादातर छोटे देशों में हिंदू समुदायों में आरएसएस के मोर्चे सक्रिय हैं, हालांकि इन आंकड़ों से उनके पैमाने या प्रभाव बड़ा जमावड़ा अमेरिका (107) में पाया जाता है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया (34) और यूनाइटेड किंगडम (26) का नंबर आता है। नेटवर्क मानचित्रण से यह संकेत मिलता है कि आरएसएस से जुड़े ये विदेश-आधारित संगठन अक्सर भारत-आधारित संगठनों के लिए वित्त पोषण (फंडिंग) का स्रोत होते हैं। उदाहरण के लिए, इंडिया डेवलपमेंट एंड रिलीफ फंड (आईडीआरएफ) अमेरिका में मैरीलैंड-स्थित एक कर-छूट प्राप्त, गैर-लाभकारी संगठन है। यह भारत में आरएसएस के कई संगठनों के लिए वित्त



पोषण का एक मुख्य स्रोत है। श्रृंखला मानचित्रण से पता चलता है कि यह कम से कम 200 संगठनों से जुड़ा हुआ है, जिसमें एक भारत, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी), वनवासी कल्याण आश्रम (वीकेए) जैसे बड़े संगठन शामिल हैं, लेकिन साथ ही देश भर में फैले छोटे एनजीओ-प्रकार के संगठनों का एक समूह भी है। इसी तरह, सपोर्ट ए चाइल्ड, यूएसए और संगठन हैं, जो संचालित रूप से भारत में आरएसएस-समर्थित संगठनों का वित्त पोषण करता है। यह सीधे विश्व हिंदू परिषद, यूएसए से जुड़ा हुआ है। कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठन कई देशों में काम कर रहे हैं। उनमें से एक ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी है, जिसकी कई प्रमुख देशों में शाखाएँ हैं। इसी तरह, विश्व हिंदू परिषद की विभिन्न देशों में सीधे सहायक संस्थाएँ हैं। आरएसएस का खुद का एक विदेशी मोर्चा है, जिसे हिंदू स्वयंसेवक संघ कहा जाता है। इसकी अधिकतर देशों में शाखाएँ हैं, जहाँ सहयोगी संगठन काम कर रहे हैं।

आरएसएस से जुड़े विदेश-आधारित संगठन जिस लक्षित आबादी के साथ काम कर रहा है, उसके हिसाब से ढालना और समझना ज़रूरी है। उदाहरण के लिए, विद्या भारती 15,000 से ज़्यादा औपचारिक रूप से मान्यता प्राप्त स्कूल, आदिवासी इलाकों में लगभग 4000 एकल शिक्षा केंद्र (अनौपचारिक एकल शिक्षक केंद्र), गरीब शहरी इलाकों में लगभग 5000 संस्कार केंद्र और 60 कॉलेज चलाती है। इन सभी में, 'नैतिक और सांस्कृतिक शिक्षा' एक मुख्य हिस्सा है -- जिसे हिंदुत्व विचारधारा की जगह नाम दिया है। संयोग से, इन संगठन पर काम करते हैं, जैसे: सेवाएं देना, स्वास्थ्य, संस्कृति, आर्थिक, रक्षा/सुरक्षा, धार्मिक गतिविधियाँ, भ्रम, मीडिया, अंतर्राष्ट्रीय मामले, वगैरह। फिर, कई संगठन ऐसे हैं, जो व्यवसाय की आधारित हैं -- व्यापारी, डॉक्टर, वकील, पूर्व सैनिक, शिक्षक, वगैरह। ये छोटे व्यक्तिगत के संगठन हैं, जिनका कोई एनजीओ संरचना नहीं है, बल्कि वे व्यक्तिगत सहकारिताएं, सामाजिक संस्थाएं या सिर्फ व्यक्तियों के संगठन हैं, जिनका कोई पंजीयन नहीं है। ये संगठन अपनी सामान्य गतिविधियों के जरिए ज़रूरतमंद लोगों को आरएसएस की ओर आकर्षित करते हैं।

आरएसएस सार्वजनिक तौर पर सिर्फ 32 सहयोगी संगठनों को मान्यता देता है, या जैसा कि वे कहते हैं, 'ये 'संघ से प्रेरित' संगठन हैं। इनमें भाजपा, विश्व हिंदू परिषद, वनवासी कल्याण आश्रम, विद्या भारती, सेवा भारती, एबीवीपी आदि जैसे सभी बड़े संगठन शामिल हैं। इनके साथ नियमित रूप से सम्मन्य बैठकें होती हैं, और इनके पदाधिकारी आरएसएस की सर्वोच्च सलाह देने वाली संस्था, अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा (प्रतिनिधियों के अखिल भारतीय

सम्मेलन) के सदस्य होते हैं।

लेकिन बाकी 2000 से ज़्यादा संगठनों के आधिकारिक तौर पर शायद ही कभी जिक्र किया जाता है, सिवाय आम शब्दों में, जैसे 'समान सोच वाले संगठन' या 'सज्जन परिषद'। मातृ संगठन से इनका संबंध या लिंक आरएसएस सदस्यों (स्वयंसेवकों) या प्रचारकों (आरएसएस के पूरा-वकती कार्यकर्ताओं) के जरिए होता है। इन संगठनों का मुख्य मकसद आरएसएस के मुख्य वैचारिक संदेशों को उन लोगों तक पहुंचाना है, जिन पर उनका असर होता है। इन मुख्य विचारों में शामिल हैं: हिंदू समाज को जगाने और उसके रेशानदार अतीत के बारे में बताकर उसकी श्रेष्ठता को स्थापित करना; सनातन धर्म से निकली अलग-अलग रस्मों, रिवाजों, परंपराओं और मौकों को अपनाना और उनका पालन करना; हिंदू समाज के सामने आने वाले रश्तरों और जोखिमों के बारे में जागरूकता पैदा करना; और आखिरकार, हिंदू राष्ट्र की स्थापना की दिशा में काम करना।

जाहिर है, इन मुख्य संदेशों को हर संगठन जिस लक्षित आबादी के साथ काम कर रहा है, उसके हिसाब से ढालना और समझना ज़रूरी है। उदाहरण के लिए, विद्या भारती 15,000 से ज़्यादा औपचारिक रूप से मान्यता प्राप्त स्कूल, आदिवासी इलाकों में लगभग 4000 एकल शिक्षा केंद्र (अनौपचारिक एकल शिक्षक केंद्र), गरीब शहरी इलाकों में लगभग 5000 संस्कार केंद्र और 60 कॉलेज चलाती है। इन सभी में, 'नैतिक और सांस्कृतिक शिक्षा' एक मुख्य हिस्सा है -- जिसे हिंदुत्व विचारधारा की जगह नाम दिया है। संयोग से, इन संगठन पर काम करते हैं, जैसे: सेवाएं देना, स्वास्थ्य, संस्कृति, आर्थिक, रक्षा/सुरक्षा, धार्मिक गतिविधियाँ, भ्रम, मीडिया, अंतर्राष्ट्रीय मामले, वगैरह। फिर, कई संगठन ऐसे हैं, जो व्यवसाय की आधारित हैं -- व्यापारी, डॉक्टर, वकील, पूर्व सैनिक, शिक्षक, वगैरह। ये छोटे व्यक्तिगत के संगठन हैं, जिनका कोई एनजीओ संरचना नहीं है, बल्कि वे व्यक्तिगत सहकारिताएं, सामाजिक संस्थाएं या सिर्फ व्यक्तियों के संगठन हैं, जिनका कोई पंजीयन नहीं है। ये संगठन अपनी सामान्य गतिविधियों के जरिए ज़रूरतमंद लोगों को आरएसएस की ओर आकर्षित करते हैं।

आरएसएस सार्वजनिक तौर पर सिर्फ 32 सहयोगी संगठनों को मान्यता देता है, या जैसा कि वे कहते हैं, 'ये 'संघ से प्रेरित' संगठन हैं। इनमें भाजपा, विश्व हिंदू परिषद, वनवासी कल्याण आश्रम, विद्या भारती, सेवा भारती, एबीवीपी आदि जैसे सभी बड़े संगठन शामिल हैं। इनके साथ नियमित रूप से सम्मन्य बैठकें होती हैं, और इनके पदाधिकारी आरएसएस की सर्वोच्च सलाह देने वाली संस्था, अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा (प्रतिनिधियों के अखिल भारतीय

सम्मेलन) के सदस्य होते हैं।

लेकिन बाकी 2000 से ज़्यादा संगठनों के आधिकारिक तौर पर शायद ही कभी जिक्र किया जाता है, सिवाय आम शब्दों में, जैसे 'समान सोच वाले संगठन' या 'सज्जन परिषद'। मातृ संगठन से इनका संबंध या लिंक आरएसएस सदस्यों (स्वयंसेवकों) या प्रचारकों (आरएसएस के पूरा-वकती कार्यकर्ताओं) के जरिए होता है। इन संगठनों का मुख्य मकसद आरएसएस के मुख्य वैचारिक संदेशों को उन लोगों तक पहुंचाना है, जिन पर उनका असर होता है। इन मुख्य विचारों में शामिल हैं: हिंदू समाज को जगाने और उसके रेशानदार अतीत के बारे में बताकर उसकी श्रेष्ठता को स्थापित करना; सनातन धर्म से निकली अलग-अलग रस्मों, रिवाजों, परंपराओं और मौकों को अपनाना और उनका पालन करना; हिंदू समाज के सामने आने वाले रश्तरों और जोखिमों के बारे में जागरूकता पैदा करना; और आखिरकार, हिंदू राष्ट्र की स्थापना की दिशा में काम करना।

जाहिर है, इन मुख्य संदेशों को हर संगठन जिस लक्षित आबादी के साथ काम कर रहा है, उसके हिसाब से ढालना और समझना ज़रूरी है। उदाहरण के लिए, विद्या भारती 15,000 से ज़्यादा औपचारिक रूप से मान्यता प्राप्त स्कूल, आदिवासी इलाकों में लगभग 4000 एकल शिक्षा केंद्र (अनौपचारिक एकल शिक्षक केंद्र), गरीब शहरी इलाकों में लगभग 5000 संस्कार केंद्र और 60 कॉलेज चलाती है। इन सभी में, 'नैतिक और सांस्कृतिक शिक्षा' एक मुख्य हिस्सा है -- जिसे हिंदुत्व विचारधारा की जगह नाम दिया है। संयोग से, इन संगठन पर काम करते हैं, जैसे: सेवाएं देना, स्वास्थ्य, संस्कृति, आर्थिक, रक्षा/सुरक्षा, धार्मिक गतिविधियाँ, भ्रम, मीडिया, अंतर्राष्ट्रीय मामले, वगैरह। फिर, कई संगठन ऐसे हैं, जो व्यवसाय की आधारित हैं -- व्यापारी, डॉक्टर, वकील, पूर्व सैनिक, शिक्षक, वगैरह। ये छोटे व्यक्तिगत के संगठन हैं, जिनका कोई एनजीओ संरचना नहीं है, बल्कि वे व्यक्तिगत सहकारिताएं, सामाजिक संस्थाएं या सिर्फ व्यक्तियों के संगठन हैं, जिनका कोई पंजीयन नहीं है। ये संगठन अपनी सामान्य गतिविधियों के जरिए ज़रूरतमंद लोगों को आरएसएस की ओर आकर्षित करते हैं।

आरएसएस सार्वजनिक तौर पर सिर्फ 32 सहयोगी संगठनों को मान्यता देता है, या जैसा कि वे कहते हैं, 'ये 'संघ से प्रेरित' संगठन हैं। इनमें भाजपा, विश्व हिंदू परिषद, वनवासी कल्याण आश्रम, विद्या भारती, सेवा भारती, एबीवीपी आदि जैसे सभी बड़े संगठन शामिल हैं। इनके साथ नियमित रूप से सम्मन्य बैठकें होती हैं, और इनके पदाधिकारी आरएसएस की सर्वोच्च सलाह देने वाली संस्था, अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा (प्रतिनिधियों के अखिल भारतीय

सम्मेलन) के सदस्य होते हैं।

लेकिन बाकी 2000 से ज़्यादा संगठनों के आधिकारिक तौर पर शायद ही कभी जिक्र किया जाता है, सिवाय आम शब्दों में, जैसे 'समान सोच वाले संगठन' या 'सज्जन परिषद'। मातृ संगठन से इनका संबंध या लिंक आरएसएस सदस्यों (स्वयंसेवकों) या प्रचारकों (आरएसएस के पूरा-वकती कार्यकर्ताओं) के जरिए होता है। इन संगठनों का मुख्य मकसद आरएसएस के मुख्य वैचारिक संदेशों को उन लोगों तक पहुंचाना है, जिन पर उनका असर होता है। इन मुख्य विचारों में शामिल हैं: हिंदू समाज को जगाने और उसके रेशानदार अतीत के बारे में बताकर उसकी श्रेष्ठता को स्थापित करना; सनातन धर्म से निकली अलग-अलग रस्मों, रिवाजों, परंपराओं और मौकों को अपनाना और उनका पालन करना; हिंदू समाज के सामने आने वाले रश्तरों और जोखिमों के बारे में जागरूकता पैदा करना; और आखिरकार, हिंदू राष्ट्र की स्थापना की दिशा में काम करना।

जाहिर है, इन मुख्य संदेशों को हर संगठन जिस लक्षित आबादी के साथ काम कर रहा है, उसके हिसाब से ढालना और समझना ज़रूरी है। उदाहरण के लिए, विद्या भारती 15,000 से ज़्यादा औपचारिक रूप से मान्यता प्राप्त स्कूल, आदिवासी इलाकों में लगभग 4000 एकल शिक्षा केंद्र (अनौपचारिक एकल शिक्षक केंद्र), गरीब शहरी इलाकों में लगभग 5000 संस्कार केंद्र और 60 कॉलेज चलाती है। इन सभी में, 'नैतिक और सांस्कृतिक शिक्षा' एक मुख्य हिस्सा है -- जिसे हिंदुत्व विचारधारा की जगह नाम दिया है। संयोग से, इन संगठन पर काम करते हैं, जैसे: सेवाएं देना, स्वास्थ्य, संस्कृति, आर्थिक, रक्षा/सुरक्षा, धार्मिक गतिविधियाँ, भ्रम, मीडिया, अंतर्राष्ट्रीय मामले, वगैरह। फिर, कई संगठन ऐसे हैं, जो व्यवसाय की आधारित हैं -- व्यापारी, डॉक्टर, वकील, पूर्व सैनिक, शिक्षक, वगैरह। ये छोटे व्यक्तिगत के संगठन हैं, जिनका कोई एनजीओ संरचना नहीं है, बल्कि वे व्यक्तिगत सहकारिताएं, सामाजिक संस्थाएं या सिर्फ व्यक्तियों के संगठन हैं, जिनका कोई पंजीयन नहीं है। ये संगठन अपनी सामान्य गतिविधियों के जरिए ज़रूरतमंद लोगों को आरएसएस की ओर आकर्षित करते हैं।

आरएसएस सार्वजनिक तौर पर सिर्फ 32 सहयोगी संगठनों को मान्यता देता है, या जैसा कि वे कहते हैं, 'ये 'संघ से प्रेरित' संगठन हैं। इनमें भाजपा, विश्व हिंदू परिषद, वनवासी कल्याण आश्रम, विद्या भारती, सेवा भारती, एबीवीपी आदि जैसे सभी बड़े संगठन शामिल हैं। इनके साथ नियमित रूप से सम्मन्य बैठकें होती हैं, और इनके पदाधिकारी आरएसएस की सर्वोच्च सलाह देने वाली संस्था, अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा (प्रतिनिधियों के अखिल भारतीय

सम्मेलन) के सदस्य होते हैं।

सम्मेलन) के सदस्य होते हैं।

मोदी के ग्यारह साल के शासन में, आरएसएस की अलग-अलग गतिविधियों जैसे चरित्र निर्माण के लिए कार्यशाला, सांस्कृतिक जागरूकता या प्राचीन विज्ञान के लिए सेमिनार और सम्मेलन वगैरह के लिए सरकारी मदद -- इसे वित्त पोषण पढ़ें -- बड़े पैमाने पर बढ़ी है। इस प्रक्रिया में, कई संगठन सामने आए हैं या मौजूदा संगठनों को अपनी गतिविधियों के लिए बढ़ावा मिला है। यह प्रक्रिया अभी भी जारी है और हो सकता है कि यह डेटाबेस में दिखाई न दे। दूसरे तरह के संगठन, जिन्हें मोदी के जमाने में बढ़ावा मिला है, वे हैं अलग-अलग हिंदुत्व उग्रवादी संगठन, जो 'गौ-रक्षा' गतिविधियों कर रहे हैं या त्योहारों और दूसरी ऐसी ही गतिविधियों का आयोजन कर रहे हैं। हो सकता है कि इनका कोई पक्का सांगठनिक ढांचा न हो और समय के साथ ये कुछ ज़्यादा स्थायी रूप ले लें। ये भी ज़्यादातर डेटाबेस में शामिल नहीं हैं।

संगठनों की एक और श्रेणी नए मीडिया-आधारित नेटवर्क हैं -- यूट्यूब चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप और चैनल, आदि। संगठनात्मक नज़रिए से यह एक प्रेरणा है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि ऐसे हजारों नेटवर्क हैं, जो सक्रिय रूप से संघ की विचारधारा फैला रहे हैं और संघ के सदस्यों द्वारा प्रभावित किए जा रहे हैं। ये भी इस डेटाबेस में शायद ही शामिल हैं।

और, आखिर में, जैसा कि शोधकर्ता खुद नेटवर्क देते हैं, ये आंकड़े सिर्फ आरएसएस नेटवर्क का हैं, न कि हिंदुत्व से जुड़े सभी संगठनों का। यह संभव है कि आरएसएस प्रचारक की अगुवाई वाली सरकार होने की वजह से, आरएसएस से जुड़े संगठन एक जैसी विचारधारा वाले, लेकिन अलग-अलग संगठनात्मक मूल वाले, दूसरे सभी संगठनों पर हावी रहेंगे। लेकिन अभी तक, ऐसे कई संगठन डेटाबेस में शामिल नहीं होंगे।

लड़ाई जारी है

यह जोर देकर कहना ज़रूरी है कि इस विशाल नेटवर्क के बावजूद -- जो फैला हुआ है और एक-दूसरे से जुड़ा हुआ भी है -- आरएसएस की विचारधारा और इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण धारा की संगठनात्मक पकड़, पूरे देश में असमान रूप से फैली हुई है। इसके बड़े हिस्से ऐसे हैं, जहाँ यह सिर्फ ऊपरी तौर पर ही पहुंचा है। आरएसएस के प्रभाव का अंदाजा न तो उसके बनाए संगठनों की संख्या से लगाया जा सकता है और न ही भाजपा की वोटों में हिस्सेदारी से। इन संगठनों से जुड़े लोग कई वजहों से इसकी तरफ आकर्षित हो सकते हैं और उन्हें आरएसएस नेटवर्क का एक छोटा-सा रूप है। इतना ज़्यादा छोटा कि जब भी आरएसएस सरसंचालक (सुप्रीम) इस क्षेत्र में आते हैं, तो वे हमेशा वहीं रुकते हैं।

यह तो बस शुरुआत है शोधकर्ताओं का मानना है कि यह आरएसएस के नेटवर्क की पूरी तस्वीर नहीं आती है। उनका ज़्यादातर काम ऑनलाइन शोध पर आधारित है और जाहिर है, ऐसे बहुत सारे संगठन हैं, जो अपनी जानकारी ऑनलाइन नहीं देते हैं। इसके अलावा, शोध में जानबूझकर कुछ पहलुओं को छोड़ दिया गया है, जैसे कि उनसे जुड़े स्कूल, जिनकी संख्या इतनी ज़्यादा है कि वे दूसरे संगठनों को 'पीछे छोड़' सकते हैं। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि स्कूल, बालवाड़ी और सांस्कृतिक केंद्र आदि आरएसएस के लिए कम ज़रूरी हैं। असल में, लोगों को अपनी पिछड़ी सोच में ढालने की आरएसएस की कोशिशों में ये शायद सबसे 'सफल' हैं।

2026 : हिंदू राष्ट्र की धमक !

(आलेख : राजेंद्र शर्मा)

आरएसएस के सौ साल पूरे होने के मौके पर देश के अलग-अलग हिस्सों में आयोजित की जा रही व्याख्यान श्रृंखला में उसके सर-संचालक, मोहन भागवत 2025 के आखिरी पखवाड़े में कोलकाता में बोल रहे थे। यहां बोलते हुए भागवत ने कुछ ऐसा कहा, जो पहली नजर में बहुतेको को आरएसएस की जानी-पहचानी लफ्फाजी का दोहराव लग सकता है, लेकिन थोड़ा गौर से देखेंगे ही उसकी खतरनाक अर्थ-ध्वनियां सुनाई देने लगती हैं। प्रकटतः तो भागवत आरएसएस का जाना-पहचाना दावा ही दुहरा रहे थे कि भारत एक हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा। रजत तक इस देश में एक व्यक्ति भी भारतीय पूर्वजों की गौरवाशाली विरासत में विश्वास करता है, तब तक भारत एक हिंदू राष्ट्र है, आदि। लेकिन, इस व्याख्यान में आरएसएस के मुखिया संभवतः पहली बार, भारत के हिंदू राष्ट्र होने के अपने दावे को, उस भारतीय संविधान के ही सामने खड़ा कर देते हैं, जो स्पष्ट रूप से भारत के एक धर्मनिरपेक्ष, बहुलतावादी राष्ट्र होने की संकल्पना पर आधारित है।

बेशक, भागवत हिंदू राष्ट्र के अपने दावे को, उपनिवेशवाद विरोधी राष्ट्रवादी संघर्ष की कोख से निकले और आंबेडकर की कलम के माध्यम से, सामाजिक बराबरी और भाईचारे की रोशनाई से लिखे गए, संविधान के साथ सीधे टकराने से बचाकर निकालने की कोशिश करने की चतुराई भी बरतते हैं और प्रकटतः यह दावा करने पर खुद को रोक भी लेते हैं कि इसके लिए संविधान की मंजूरी की जरूरत नहीं है कि रूढ़िदृष्टान्त एक हिंदू राष्ट्र है। फिर भी वह संविधान की मंजूरी होने या न होने से फर्क ही नहीं पड़ने की इस झूठी मुद्रा पर ही नहीं रुके रहते हैं। वह खुलेआम राजनीति के मैदान में उतरते हुए, इसकी अनिष्टकर संभावना की ओर भी इशारा करते हैं कि 'अगर संसद कभी संविधान में संशोधन कर वह शब्द जोड़ने का फैसला करती है...' ; वह शब्द यानी हिंदू राष्ट्र। यह दूसरी बात है कि इस संभावना के जिक्र के साथ भी वह यह जोड़ना नहीं भूलते हैं कि संसद अगर ऐसा 'न भी करे, तो हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें उस शब्द की परवाह नहीं है, क्योंकि हम हिंदू हैं और हमारा राष्ट्र हिंदू राष्ट्र है। यही सच्चाई है।'

सीधी-सरल भाषा में इस पूरी शाब्दिक कसरत का अर्थ यही है कि मोहन भागवत का संगठन, यह जानते-समझते हुए भी कि यह भारत के वर्तमान संविधान के खिलाफ है, भारत को हिंदू राष्ट्र मानता है और सबसे मनवाने के लिए यानी हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, काम कर रहा है और करता रहेगा। इसके लिए वह संविधान के ही बदले जाने के भरोसे बैठा तो नहीं रहेगा। हां! संविधान और उसकी भाषा बोलने लगे तो कहना ही क्या? मोदी-शाह की भाजपा के लिए संघ की सीवी सीएल गिरीह पर भागवत ने अगला टास्क तय कर दिया है -- संविधान बदलकर कर उसमें वह शब्द (हिंदू राष्ट्र) जुड़वाना!

और साल के उसी अंतिम पखवाड़े में मोदी-शाह की हुकूमत क्या कर रही थी? देश की आबादी का कुल 2.3 फीसदी हिस्सा बनाने वाले

ईसाइयों के सबसे बड़े धार्मिक त्यौहार पर, जो वैसे भी सबसे प्रेम तथा सहैद्र व मेल-जोल के संदेश के लिए ही जाना जाता रहा है, मोदी-शाह की भाजपा समेत, समूचे आरएसएस विचार परिवार के सरासर अकारण हमलों को, सामान्य बनाने की कोशिश की जा रही थी। भागवत के उपदेश की तरह, इस मामले में मोदी-शाह की हुकूमत दुहरी चाल चल रही थी। एक ओर संघ विचार परिवार के हिस्से के तौर पर, सिर्फ बजरंग दल, विहिप आदि जैसे कथित रूप से हाशिए के संगठन ही नहीं, केन्द्र में मोदीशाही से लेकर, उत्तर प्रदेश में योगीशाही तक, धर्मनिरपेक्ष संविधान के अंतर्गत चुनी गयी भाजपायी सरकारें तक, एक त्यौहार के रूप में क्रिसमस की ही नकल करने में लगी हुई थीं। केन्द्र ने 25 दिसंबर को क्रिसमस की जगह तथ्याकथित सुशासन विकास मनाने से जो शुरुआत की थी, उसे इस बार उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड जैसे भाजपा-शासित राज्यों में क्रिसमस की छुट्टी ही रह कर देने तक पहुंचा दिया। यहां इस मौके पर व्यापक स्तर पर अटलबिहारी वाजपेयी का जन्म दिन मनाया गया, जिसके लिए बच्चों को खासतौर पर स्कूलों में बुलाया गया। इस मौके पर स्वयं प्रधानमंत्री ने लखनऊ में एक विशाल कार्यक्रम में 230 करोड़ रु. की लागत से बने "राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल" और हार्मनी पार्क का उद्घाटन किया।

अपने "हिंदू राज" की, वाजपेयी के जन्मदिन से क्रिसमस को प्रतिस्थापित करने की इस तरह की कोशिशों से प्रेरणा पाकर, भाजपा समेत संघ परिवार के विभिन्न संगठनों ने देश के विभिन्न हिस्सों में, जाहिर है कि ज्यादातर भाजपा-शासित राज्यों में, क्रिसमस के आयोजनों को अभूतपूर्व हलकों और तोड़-फोड़ का निशाना बनाया। असम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, दिल्ली, ओडिशा, राजस्थान, उत्तराखंड तथा कुछ अन्य राज्यों में, क्रिसमस की पूर्व-संध्या से लेकर क्रिसमस के दिन तक, हमले की ऐसी घटनाएं घट ही रही थीं। शांतिग मॉल, बाजार आदि, सार्वजनिक स्थलों पर क्रिसमस की सजावट पर तोड़-फोड़ के जरिए विशेष ध्यान से यह व्यापक संदेश देने की कोशिश की गयी कि हिंदू राज में, गैर-हिंदू अपने धार्मिक त्यौहार मनाते, रीति-रिवाजों का पालन करते, कर्म-कांड करते, सार्वजनिक रूप से दिखाई नहीं देने चाहिए। अल्पसंख्यक हों भी तो अदृश्य होकर रहें, दिखाई सिर्फ हिंदू देने चाहिए। आरएसएस के सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांतकार माने जाने वाले, गोलवालकर ने हिंदू राष्ट्र में रहने वाले अल्पसंख्यकों के लिए, ठीक यही "मर्यादा" तय की है।

बेशक, क्रिसमस पर हमले की ऐसी घटनाएं पहली बार नहीं हो रही थीं। पहले कभी-कभार, स्थानीय कारणों से होने वाली इस तरह की घटनाएं, शासन से एक प्रकार से खुली छूटी, आंखीआंशुवद हासिल होने के कारण, मोदीशाही में लगातार और तेजी से बढ़ती गयी हैं। इस क्रिसमस पर इन घटनाओं में करीब छः गुनी बढ़ोतरी होने की खबर है। संघ परिवार की दोहरी चाल के अनुरूप, खुद प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश में औपचारिक रूप से क्रिसमस की जगह वाजपेयी के जन्म दिन को बैठाने के कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए रवाना होने से पहले, राजधानी दिल्ली में बड़े भक्तिभाव से एक गिराव में जाकर क्रिसमस की विशेष प्रार्थना में शामिल हुए। उन्होंने अपने क्रिसमस के इस आयोजन में शामिल होने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर डाला और प्रेम व सद्भाव को क्रिसमस का मूल संदेश बताते हुए, सार्वजनिक रूप से क्रिसमस की शुभकामनाएं भी दीं। दूसरी ओर, अपने संघ परिवारियों के हमलों से क्रिसमस और ईसाइयों को बनाने के लिए खुद उन्होंने और उनके राज ने, कुछ भी नहीं किया। यहां तक कि न तो प्रधानमंत्री को इसकी अपील तक करना गवारा हुआ कि ऐसे हमले नहीं होने चाहिए और न उनके नंबर दो, गृहमंत्री को ऐसी गुंडागर्दी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की धमकी तक देना गवारा हुआ। हैरानी की बात नहीं है कि इन हमलों के लिए, भाजपा-शासित राज्य में पुलिस ने शायद ही किसी पर कोई कार्रवाई की है! जब लक्ष्य हिंदू राज में अल्पसंख्यकों की ही अदृश्य करना है, उन पर हमलों को कैसे दर्ज होने दिया जा सकता है। गोलवालकर की कल्पना के लिए राष्ट्र की

2026 की दहलीज पर: भारत की आर्थिक कहानी और वैश्विक भविष्य की तस्वीर

-सुनील कुमार महला

साल 2025 से 2026 में कदम रखना केवल कैलेंडर का पन्ना पलटना भर नहीं है, बल्कि यह आत्ममूल्यांकन और नव-आरंभ का अवसर है। वास्तव में सच तो यह है कि यह समय उन सपनों और लक्ष्यों को फिर से साधने का है, जो बीते वर्ष परिस्थितियों, सीमाओं या संकोच के कारण अधूरे रह गए। साथ ही, यह आने वाली चुनौतियों को पहचानकर उनके लिए स्वयं को मानसिक, बौद्धिक और व्यवहारिक रूप से तैयार करने की प्रेरणा देता है। नया वर्ष हमें अतीत से सीख लेकर भविष्य की ओर आशा, संकल्प और सकारात्मक दृष्टि के साथ आगे बढ़ने का संदेश देता है। कोई भी साल पूरी तरह आदर्श नहीं होता, और 2025 भी इसका अपवाद नहीं रहा। हालांकि, उससे मिली सीख नए वर्ष में दिशा दिखा सकती है। बीता साल आर्थिक लिहाज से भारी उतार-चढ़ाव से भरा रहा। लंबी तेजी के बाद शेयर बाजार में सुस्ती आई, वहीं अमेरिका में डोनाल्ड ट्रम्प के दोबारा सत्ता में आने के साथ वैश्विक को लेकर सख्त रुख अपनाया गया। इन चुनौतियों के बीच भारत ने संतुलन और दृढ़ता का परिचय दिया। ट्रंप के दबाव के बावजूद रूस के साथ संबंधों को प्राथमिकता देकर भारत ने स्पष्ट किया कि उसकी विदेश नीति स्वतंत्र है। इसी अवधि में रूस, यूक्रेन और ओमान के साथ महत्वपूर्ण समझौते भी हुए, जो भारत की कूटनीतिक सक्रियता और आत्मनिर्भर सोच को दर्शाते हैं।

जीएसटी सुधार और भारतीय अर्थव्यवस्था- जैसा कि पाठक जानते होंगे कि पिछले साल देश के भीतर जीएसटी 2.0 जैसे बड़े सुधार लागू किए गए, जिससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था को अच्छी खासी मजबूती मिली। इसका असर यह रहा कि दूसरी तिमाही में भारत की आर्थिक वृद्धि 8.2% रही। (साल के अंत तक भारत के जापान को पीछे छोड़कर लगभग

4.18 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के साथ दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का अनुमान उसकी तेज और निरंतर आर्थिक वृद्धि पर आधारित है। कहना गलत नहीं होगा कि मजबूत घरेलू मांग, बढ़ता मध्यम वर्ग, सरकारी पूंजीगत खर्च, बुनियादी ढांचे में निवेश और जीएसटी जैसे संरचनात्मक सुधारों ने आर्थिक गतिविधियों को गति दी है। साथ ही, वैश्विक सप्लाई चेन में बदलाव और भारत को वैकल्पिक उत्पादन केंद्र के रूप में मिल रहा भरसा निवेश और निर्यात को बढ़ावा दे रहा है। इसके विपरीत, जापान की अर्थव्यवस्था धीमी वृद्धि, घटती आबादी और सीमित घरेलू मांग से जूझ रही है। इन सभी कारणों के चलते भारत की जीडीपी तेजी से बढ़ रही है और मौजूदा अनुमानों के अनुसार वह वर्ष के अंत तक जापान को पीछे छोड़कर वैश्विक आर्थिक रैंकिंग में चौथे स्थान पर पहुंच सकता है। इसके अलावा, अन्य देशों के साथ हुई व्यापार संधियों और अमेरिका के साथ होने वाला समझौता पूरा होने से आगे चलकर अर्थव्यवस्था की रफ्तार और तेज होने की उम्मीद है। दूसरे शब्दों में कहें तो वैश्विक स्तर पर आर्थिक चुनौतियों और अनिश्चितताओं के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था के मजबूत बने रहने की संभावना है। इसका मुख्य कारण देश के भीतर मजबूत मांग, महंगाई का नियंत्रण में रहना और सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक की संतुलित आर्थिक नीतियां हैं।

अर्थव्यवस्था के मामले में 2030 तक जर्मनी को पछाड़ देगा भारत:- अनुमान है कि भारत 2030 तक जर्मनी को भी पछाड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बन जाएगा। सरकार ने भरसा जताया है कि मजबूत आर्थिक नींव के साथ, भारत की जीडीपी 2030 तक 7.3 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगी। आरबीआई की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट के

अनुसार, देश के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक अच्छी स्थिति में हैं, उनके पास पर्याप्त पूंजी और नकदी भंडार हैं, खराब कर्ज में कमी आई है और उनका मुनाफा भी मजबूत बना हुआ है। यहां पाठकों को जानकारी देना चाहूंगा कि केंद्रीय बैंक के दबाव परीक्षण से यह भी स्पष्ट हुआ है कि प्रतिकूल हालात में भी बैंक संभावित संरचनात्मक सुधारों ने आर्थिक गतिविधियों को गति दी है। हालांकि, निकट भविष्य में भू-राजनीतिक तनाव और वैश्विक व्यापार में अनिश्चितता से कुछ जोखिम बने हुए हैं, फिर भी कुल मिलाकर भारत की वित्तीय प्रणाली स्थिर और सुरक्षित बनी हुई है। हाल फिलहाल कहना चाहूंगा कि देश की अर्थव्यवस्था की तरह ही हमारे देश ने पिछले साल यानी कि वर्ष 2025 में सीमा से जुड़ी चुनौतियों का भी मजबूती से सामना किया। पाकिस्तान में मौजूद आतंकवादियों के खिलाफ किया गया 'ऑपरेशन सांद्र' इस बात का उदाहरण था कि भारत जरूरत पड़ने पर कड़ा कदम भी उठा सकता है और साथ ही संयम भी बरतता है। इससे भारत की सैन्य क्षमता और जिम्मेदार रवैये दोनों का संदेश गया। पड़ोसी देशों से रिश्तों को बात करे तो चीन के साथ लंबे समय से चला आ रहा तनाव कुछ हद तक कम हुआ। करीब पाँच साल बाद दोनों देशों के बीच सीधी उड़ानें शुरू हुईं और प्रधानमंत्री मोदी शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) की बैठक में शामिल होने चीन गए। वहीं बांग्लादेश के हालात चिंता का कारण बने रहे। उम्मीद है कि फरवरी में होने वाले चुनावों के बाद वहां बनने वाली नई सरकार भारत के साथ अच्छे और स्थिर रिश्तों की अहमियत को समझेगी। साल भर देश में असहिष्णुता और धर्म-

जाति के आधार पर भेदभाव से जुड़ी कई घटनाएँ सामने आईं। साल के अंत में क्रिसमस के दौरान कुछ जगहों पर हुई तोड़फोड़ की तस्वीरों ने देश की छवि को नुकसान पहुँचाया। इसके साथ ही भारी बारिश, भूस्खलन, वायु प्रदूषण और अरबवली से जुड़े मामलों के कारण पर्यावरण पूरे साल एक बड़ा मुद्दा बना रहा। एसआइआर को लेकर भी राजनीतिक विवाद देखने को मिला। राहत की बात यह रही कि इन सभी विषयों पर जनता पहले से ज्यादा जागरूक और सजग नजर आई।

इस साल भारत से बड़ी उम्मीदें जुड़ी हैं:- अंत में यही कहूंगा कि नये साल में यानी कि वर्ष 2026 में भारत से कई बड़ी उम्मीदें जुड़ी हैं। सबसे बड़ी आशा यह है कि देश तेज और स्थिर आर्थिक वृद्धि के साथ दुनिया की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं में अपनी स्थिति और मजबूत करेगा, जिससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और आम लोगों की आय में सुधार आएगा। बुनियादी ढांचे, मैन्यूफैक्चरिंग, स्टार्टअप और डिजिटल अर्थव्यवस्था में निरंतर निवेश से विकास को गति मिलने की उम्मीद है। साथ ही, शिक्षा, कौशल विकास और तकनीक-विशेषकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ) के क्षेत्र में भारत वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान और मजबूत कर सकता है। सामाजिक मोर्चे पर उम्मीद है कि समावेशी विकास, सामाजिक सौहार्द और सुशासन पर ध्यान बड़ेगा, जबकि पर्यावरण संरक्षण और जलवायु संतुलन के प्रयास भी मजबूत होंगे। कुल मिलाकर, 2026 से अपेक्षा है कि भारत विकास और स्थिरता के बीच संतुलन बनाते हुए नागरिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने की दिशा में ठोस कदम बढ़ाएगा।

सुनील महला, फ्रीलांस राइटर, कॉलमिस्ट व युवा साहित्यकार, पिथौरागढ़, उत्तराखंड

टाटा स्टील का स्ट्रैट बार मिल 31 दिसंबर को अचानक हुआ बंद, 700 लोग हुए बेरोजगार



कार्तिक कुमार परिष्ठा, स्टेट हेड-झारखंड

जमशेदपुर, झारखंड के सरायकेला जिला अन्तर्गत महत्वपूर्ण क्षेत्र आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र स्थित टाटा स्टील की इकाई स्ट्रेट बार मिल (पूर्व में उषा मार्टिन) बुधवार 31 दिसंबर से अचानक बंद कर दी गयी। इसके साथ ही करीब 700 कामगार बेरोजगार हो गए। इसकी खबर मिलते ही कामगार आक्रोशित हो गये और मिल गेट पर प्रदर्शन किया। बुधवार सुबह इयूटी पर कामगार पहुंचे तो कंपनी बंद की सूचना से थडक गये। गेट पर हंगामा के साथ प्रदर्शन शुरू कर दिया। कर्मचारियों ने प्रबंधन पर बिना पूर्व सूचना के बंद करने का आरोप लगाया। बताया कि वर्ष

1999 से कई कामगार यहां कार्यरत हैं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया। अब इस उद्यम में उन्हें कहां नौकरी मिलेगी। कंपनी बंद करने से पूर्व उनका बकाया वेतन समेत अन्य सुविधाओं का भी भुगतान नहीं किया गया है। टाटा स्टील की ओर से जब उषा मार्टिन के इस प्लांट का अधिग्रहण किया था, तब यह भरसा दिया गया था कि प्लांट का संचालन जारी रहेगा। साथ ही किसी की नौकरी नहीं जाएगी। वर्तमान में यह प्लांट वेंडर कंपनी आरके एंटरप्राइजेज के मध्यम से संचालित हो रही थी, जिसके तहत 165 श्रमिक कार्यरत थे। वहीं, अन्य ठेकेदारों के अधीन कार्यरत कामगारों को मिलाकर करीब 6 सौ से अधिक बेरोजगार हो गए हैं।

हजारीबाग सेंट्रल जेल से बिजली सिक्क्यूरिटी फेंसिंग तोड़कर आधी रात तीन कैदी हुए फरार

लोकनायक जयप्रकाश नारायण पर नामित जेल। जहां वे अंग्रेजों को चकमा देकर

दीपावली के रात हुए छे फरार कार्तिक कुमार परिष्ठा, स्टेट हेड-झारखंड

रांची। झारखंड का उच्च सुरक्षा दायरे का जेल माना जाने वाला ऐतिहासिक जेल लोकनायक जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारा से तीन कैदी सुरक्षा घेरा को तोड़ते हुए फरार हो गए हैं। यह तीनों कैदी धनबाद के हैं, जिसकी पुष्टि जेल अधीक्षक चंद्रशेखर सुमन ने की है। इस घटना ने पूरे प्रशासनिक तंत्र को शकते में ला दिया है। यह जेल हाई सिक्क्योरिटी के लिए जाना जाता है। जहां खूंखार कैदी और नक्सलियों को रखा जाता है, इसके साथ ही कई विचाराधीन हाई प्रोफाइल कैदी भी जेल में बंद हैं। ऐसे में तीन कैदी के लापता होने के बाद सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठना शुरू हो चुका है। हजारीबाग जेल की सुरक्षा व्यवस्था को हाल के दिनों में और भी अधिक दुरुस्त किया गया था। सुरक्षा के नजर जेल आईजी ने पिछले दिनों कार्रवाई करते हुए 12 सुरक्षा कर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया था। उसके बाद से ही सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त कर दी गई थी। लेकिन इस घटना ने फिर एक बार हजारीबाग जेल प्रशासन पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवालिया निशान खड़ा हो गया है। तीनों फरार कैदी चार नंबर गुम्टी से एक रस्सी के सहारे फरार हुए हैं। जेल के पीछे साइड से एक रस्सी भी देखा गया, जो टैट हाउस में उपयोग किए जाने वाला कपड़े टुकड़े से बनाया गया। घटनास्थल को देखकर यह बताया जा सकता है कि रस्सी पहले अंदर से बाहर फेंका गया है। वह रस्सी किसी सामान से हाई सिक्क्योरिटी जेल के बाहर सुरक्षा व्यवस्था के तार से फंसा है। जहां से यह तीनों कैदी फरार हुए हैं। प्राप्त सूचना के अनुसार यह घटना रात के करीब 1 बजे से 2 बजे के बीच की है। शौचालय जाने के बहाने तीनों कैदी बाहर निकले और शौचालय के खिड़की से फरार हुए हैं। जेल के बाहर हिस्से में भी तार का फेंसिंग है, जो टूटा हुआ है। हालांकि लोगों का कहना है फेंसिंग पहले से ही टूटा हुआ था। जेल की सुरक्षा के मद्देनजर इसके चार दीवारी पर बिजली का तार भी लगाया गया है। जहां 24 घंटे बिजली प्रवाहित होती है। इसके बावजूद बिजली तार की सुरक्षा घेरे को तोड़कर कैदी फरार हो गए। घटना के बाद जेल के चारों तरफ सुरक्षा बढ़ा दी गई है। किसी को भी मुलाकात करनी की इजाजत नहीं दी जा रही है। जितने भी कैदी हैं, उन्हें वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। जिले के वरीय पदाधिकारी जिसमें एसडीओ, एसडीपीओ समेत वरीय अधिकारी जेल के अंदर ही जांच कर रहे हैं। मामले में जेल अधीक्षक चंद्रशेखर सुमन ने फोने पर इंटिवीवों की जानकारी दी है कि जेल से 3 कैदी फरार हुए हैं। लेकिन अभी इसके बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं दी जा सकती है कि घटना कैसे घटी है। मामले की तपतीशी की जा रही

ओडिशा का समुद्री इतिहास 2026 में एक नया रूप लेगा

मनोरंजन शासमल, स्टेट हेड ओडिशा

भुवनेश्वर: पुराने कालिंग में साध्वियों ने समुद्री व्यापार कैसे किया? वे नावों में सवार होकर विशाल समुद्र में कैसे गए? ओडिशा की धरती से साध्वियों ने बिना किसी मशीनी सिस्टम की मदद के दक्षिण-पूर्व एशिया के अलग-अलग देशों में व्यापार करने के लिए कैसे यात्रा की? अगर आज की पीढ़ी, जिसने किताबों में ये सारी कहानियाँ पढ़ी हैं, को अतीत के इस नजारे को अपनी आँखों से फिर से देखने का मौका मिले, तो यह एक सपने के सच होने जैसा लगेगा। एसा ही होगा। 'INSV Kaundinya' कार्तिक पूर्णिमा 2026 पर एक बार फिर ओडिशा की समुद्री परंपरा के इतिहास को हमारे सामने लाएगा। सिलाई के हुनर से पारंपरिक स्टाइल में बना यह जहाज 'INSV Kaundinya' कार्तिक पूर्णिमा पर ओडिशा से बाली जाएगा, एसा जहाज बनाने वाले और प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार समिति के सदस्य संजीव सान्याल ने कहा। संजीव के एक देश भर में मशहूर पॉडकास्ट पर यह राय देने के बाद ओडिशा में इस पर चर्चा शुरू हो गई है। हाल ही में, इस जहाज ने गुजरात के पोर्टबंदर में अओमान के मस्कट तक एक ऐतिहासिक यात्रा शुरू की। यह यात्रा भारतीय नाविकों द्वारा लिए गए सदियों पुराने समुद्री रास्ते को दोहराएगी, जो लोग असफलता से डरते हैं, वे अक्सर प्रयास ही नहीं करते। और जो प्रयास नहीं करते, वे कभी आगे नहीं बढ़ते। नया साल जोखिम लेने और सीखते हुए आगे बढ़ने का नाम है।



समीरवी समाज कोरेमला बडेर मुख्य द्वार के शीला पुजा अर्चना किया इस अवसर पर उपस्थित संरक्षक प्रभुराम परिहारिया, अध्यक्ष कालुराम काग, सह सचिव राजाराम गेहलोत कोषाध्यक्ष पोकरराम पंवार, सलाहकार पुनाराम हाब्बड़, हुवमाराम सेपटा, पुजारी पोकरराम काग व अन्य।

सफदरजंग अस्पताल में सीएसआर सहयोग से डायग्नोस्टिक सेवाओं को मिली मजबूती, सीटी स्कैन

स्वतंत्र सिंह भुल्लार नई दिल्ली

नई दिल्ली। वीएमएससी एवं सफदरजंग अस्पताल में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) के अंतर्गत नई सीटी स्कैन मशीन का उद्घाटन किया गया। यह पहल पीटीसी इंडिया लिमिटेड, पीटीसी फाउंडेशन तथा डॉक्टर्स फॉर यू (DFY) के सहयोग से साकार हुई है, जिससे अस्पताल की डायग्नोस्टिक क्षमताओं में उल्लेखनीय वृद्धि होगी और रोगियों को समय पर सटीक जांच सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी। इस अवसर पर कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में डॉ. मनोज कुमार झावर, चेयरमैन एवं मैनेजिंग डायरेक्टर, पीटीसी इंडिया लिमिटेड, सुश्री रश्मि शर्मा, चेयरपर्सन, सीएसआर समिति, पीटीसी इंडिया लिमिटेड तथा श्री पंकज गोयल, एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर, पीटीसी इंडिया लिमिटेड उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉ. संदीप बंसल, निदेशक, वीएमएससी एवं सफदरजंग अस्पताल ने की, जो एक प्रख्यात हृदय रोग विशेषज्ञ होने के साथ-साथ अपने करुणामय एवं रोगी-केंद्रित दृष्टिकोण के लिए व्यापक रूप से सम्मानित हैं। सीटी स्कैन मशीन का उद्घाटन डॉ. रजत जैन, अध्यक्ष, डॉक्टर्स फॉर यू (DFY) — जो इस



परियोजना की क्रियान्वयन एजेंसी है — तथा डॉ. चारु बंबा, चिकित्सा अधीक्षक की उपस्थिति में संपन्न हुआ। इस अवसर पर संबोधित करते हुए डॉ. संदीप बंसल ने पीटीसी इंडिया लिमिटेड का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि नई सीटी स्कैन मशीन के स्थापित होने से अस्पताल की जांच क्षमता में अत्यधिक वृद्धि होगी। इससे न केवल जांच की प्रतीक्षा अवधि कम होगी, बल्कि हजारों रोगियों को समय पर एवं सटीक निदान उपलब्ध हो सकेगा, जो उपचार की गुणवत्ता में भी सुधार लाएगा। डॉ. मनोज कुमार झावर, चेयरमैन एवं मैनेजिंग डायरेक्टर, पीटीसी इंडिया लिमिटेड ने

अपने संबोधन में कहा कि पीटीसी अपने सीएसआर कार्यक्रमों के माध्यम से समाज में स्थायी और सकारात्मक प्रभाव उत्पन्न करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवा पीटीसी के प्रमुख सीएसआर फोकस क्षेत्रों में से एक है और सफदरजंग अस्पताल में सीटी स्कैन मशीन की स्थापना आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को उन्नत जांच सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में कंपनी की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। वहीं सुश्री रश्मि शर्मा, चेयरपर्सन, सीएसआर समिति, पीटीसी इंडिया लिमिटेड ने कहा कि सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को सुदृढ़ करने में कॉर्पोरेट

क्षेत्र की जिम्मेदार भागीदारी अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि जब सीएसआर पहलें संस्थागत आवश्यकताओं के अनुरूप होती हैं, तो उनका सीधा लाभ रोगियों के बेहतर उपचार और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार के रूप में सामने आता है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉ. रजत जैन, अध्यक्ष, डॉक्टर्स फॉर यू (DFY) ने सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों, कॉर्पोरेट सझेदारों एवं क्रियान्वयन एजेंसियों के बीच मजबूत समन्वय की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इस प्रकार का सहयोग न केवल रोगियों के समयबद्ध क्रियान्वयन को सुनिश्चित करता है, बल्कि सरकारी अस्पतालों को बड़े पैमाने पर गुणवत्तापूर्ण डायग्नोस्टिक सेवाएं प्रदान करने में भी सक्षम बनाता है। इस उद्घाटन समारोह में सहयोगी संस्थाओं की सीएसआर समितियों के सदस्य, डॉ. अमिता मलिक, विभागाध्यक्ष (रेडियोलॉजी), चिकित्सक, फैंकट्टी सदस्य, नर्सिंग स्टाफ तथा छात्र-छात्राएँ भी उपस्थित रहे। वीएमएससी एवं सफदरजंग अस्पताल ने इस अवसर पर सीएसआर सहयोग के प्रभावी एवं पारदर्शी उपयोग के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि भविष्य में भी रोगी-केंद्रित सेवाओं के विस्तार और उन्नत चिकित्सा जांच सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए ऐसे प्रयास लगातार जारी रहेंगे।

नूतन वर्ष: नए सपने, नई उम्मीदें

डॉ सत्यवान सौरभ

नया वर्ष केवल कैलेंडर की तारीख बदलने का नाम नहीं है। यह हमारे जीवन में एक ठहराव की तरह आता है—जहाँ हम पीछे मुड़कर देखते हैं, वर्तमान को समझते हैं और भविष्य की दिशा तय करते हैं। हर नया साल अपने साथ नई उम्मीदें, नए संकल्प और नई संभावनाएँ लेकर आता है। यह वह क्षण होता है जब मनुष्य अपने भीतर झाँकता है और स्वयं से यह प्रश्न करता है: 'संस्कार में 2026 तक US\$ 500 बिलियन की इकॉनमी के साथ एक समृद्ध ओडिशा बनाने और राज्य को 'मिस्ड इकॉनमी' की ओर ले जाकर इसे टॉप 5 विकसित राज्यों में लाने का लक्ष्य रखा है। इसलिए, मुख्यमंत्री के तौर पर, उन्होंने नॉलेज-ड्रिवन इंडस्ट्रीज और सर्विस सेक्टर को ज्यादा महत्व देकर इसके तेजी से विकास के लिए काम करने का निर्देश दिया है। सभी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरों को राज्य में इंडस्ट्रियलाइजेशन के तेजी से विकास के लिए अलग-अलग प्रोसेस को फास्ट-ट्रैक करने के निर्देशों पर जोर दिया गया है। इसी तरह, उन्होंने अगले 2 साल के अंदर सभी खाली सरकारी पोस्ट भरने का आदेश दिया है। उन्होंने काबिल और ट्रेड अधिकारियों की सर्विस पर जोर दिया है और भ्रष्ट, नाकाबिल और गैर-जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों की पहचान करके उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहा है। उन्होंने कंपलसरी सर्विस बंद करने का भी आदेश दिया है। यह मुख्यमंत्री के एडमिनिस्ट्रेशन को ट्रांसपेरेंट, कुशल और मोबाइल बनाने के पक्के इरादे को दिखाता है। इसके साथ ही, अलग-अलग प्रोजेक्ट्स को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए रेगुलर रिव्यू और इवैल्यूएशन पर जोर दिया गया है। रिसर्च और डेवलपमेंट पर जोर देने के लिए, नवकृष्ण चौधरी डेवलपमेंट रिसर्च सेंटर को सेंटर ऑफ एक्सिलेंस के तौर पर डेवलप करने का आदेश दिया गया है। मुख्यमंत्री ने सभी तरह के सरकारी काम, खासकर नोटिस, नोटिफिकेशन और चिट्ठियों का लेन-देन सिर्फ ओडिशा भाषा में करने का आदेश दिया है। सेक्रेटरीएट से लेकर ब्लॉक लेवल तक के सभी अधिकारियों को इस निर्देश का सख्ती से पालन करने को कहा गया है। शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभागों से इस बारे में माफ़ी मांगने को भी कहा गया है। इसलिए, मुख्यमंत्री ने ओडिशा को ऑफिशियल भाषा के तौर पर इस्तेमाल करने के कमिटेट का भी मैसेज दिया है।



नया वर्ष केवल कैलेंडर की तारीख बदलने का नाम नहीं है। यह हमारे जीवन में एक ठहराव की तरह आता है—जहाँ हम पीछे मुड़कर देखते हैं, वर्तमान को समझते हैं और भविष्य की दिशा तय करते हैं। हर नया साल अपने साथ नई उम्मीदें, नए संकल्प और नई संभावनाएँ लेकर आता है। यह वह क्षण होता है जब मनुष्य अपने भीतर झाँकता है और स्वयं से यह प्रश्न करता है: 'संस्कार में 2026 तक US\$ 500 बिलियन की इकॉनमी के साथ एक समृद्ध ओडिशा बनाने और राज्य को 'मिस्ड इकॉनमी' की ओर ले जाकर इसे टॉप 5 विकसित राज्यों में लाने का लक्ष्य रखा है। इसलिए, मुख्यमंत्री के तौर पर, उन्होंने नॉलेज-ड्रिवन इंडस्ट्रीज और सर्विस सेक्टर को ज्यादा महत्व देकर इसके तेजी से विकास के लिए काम करने का निर्देश दिया है। सभी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरों को राज्य में इंडस्ट्रियलाइजेशन के तेजी से विकास के लिए अलग-अलग प्रोसेस को फास्ट-ट्रैक करने के निर्देशों पर जोर दिया गया है। इसी तरह, उन्होंने अगले 2 साल के अंदर सभी खाली सरकारी पोस्ट भरने का आदेश दिया है। उन्होंने काबिल और ट्रेड अधिकारियों की सर्विस पर जोर दिया है और भ्रष्ट, नाकाबिल और गैर-जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों की पहचान करके उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहा है। उन्होंने कंपलसरी सर्विस बंद करने का भी आदेश दिया है। यह मुख्यमंत्री के एडमिनिस्ट्रेशन को ट्रांसपेरेंट, कुशल और मोबाइल बनाने के पक्के इरादे को दिखाता है। इसके साथ ही, अलग-अलग प्रोजेक्ट्स को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए रेगुलर रिव्यू और इवैल्यूएशन पर जोर दिया गया है। रिसर्च और डेवलपमेंट पर जोर देने के लिए, नवकृष्ण चौधरी डेवलपमेंट रिसर्च सेंटर को सेंटर ऑफ एक्सिलेंस के तौर पर डेवलप करने का आदेश दिया गया है। मुख्यमंत्री ने सभी तरह के सरकारी काम, खासकर नोटिस, नोटिफिकेशन और चिट्ठियों का लेन-देन सिर्फ ओडिशा भाषा में करने का आदेश दिया है। सेक्रेटरीएट से लेकर ब्लॉक लेवल तक के सभी अधिकारियों को इस निर्देश का सख्ती से पालन करने को कहा गया है। शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभागों से इस बारे में माफ़ी मांगने को भी कहा गया है। इसलिए, मुख्यमंत्री ने ओडिशा को ऑफिशियल भाषा के तौर पर इस्तेमाल करने के कमिटेट का भी मैसेज दिया है।

हम वही बनना चाहते हैं जो समाज चाहता है, या वह जो हमारी आत्मा चाहती है? सपने छोटे भी हो सकते हैं—जैसे खुद को स्वस्थ रखना, परिवार को समय देना, या खुद के लिए थोड़ा वक्त निकालना। हर सपना बड़ा मंच या बड़ी पहचान नहीं मांगता; कई बार सबसे बड़ा सपना होता है—संतुलित और शांत जीवन। नई उम्मीदें: बाहरी नहीं, आंतरिक उम्मीदें अक्सर हम दूसरों से जोड़ लेते हैं—कि कोई बदले, परिस्थितियाँ सुधरे, सिस्टम ठीक हो जाए। लेकिन नया वर्ष हमें यह याद दिलाता है कि सबसे मजबूत उम्मीद वह होती है जो अपने भीतर से जन्म लेती है। जब हमें खुद पर भरोसा होता है, तब हालात चाहे जैसे हों, हम रास्ता निकाल लेते हैं। आंतरिक उम्मीद का अर्थ है—यह विश्वास कि मैं बदल सकता/सकती हूँ, मैं सीख सकता/सकती हूँ और मैं बेहतर बन सकता/सकती हूँ। यह उम्मीद हमें निराशा से बाहर निकालती है और असफलता के बाद भी खड़ा होने की ताकत देती है। खुद से रिश्ता: नए साल की सबसे बड़ी शुरुआत नए साल में सबसे पहला रिश्ता जिसे सुधारने की जरूरत होती है, वह है—खुद से रिश्ता। हम दूसरों की गलतियों को तो तुरंत देख लेते हैं, लेकिन अपनी कमियों से अक्सर बचते रहते हैं। नया वर्ष आत्मस्वीकृति और आत्मसुधार का संतुलन सिखाता है। खुद से ईमानदारी का मतलब यह नहीं कि हम खुद को कठपुतले में खड़ा करें, बल्कि यह कि हम अपनी सच्चाई को स्वीकार करें। अपनी सीमाओं को समझें, अपनी क्षमताओं को पहचानें और खुद के प्रति करुणा रखें। जब हम खुद को समझने लगते हैं, तब दुनिया से हमारी अपेक्षाएँ भी यथार्थवादी हो जाती हैं। रिश्ते: मात्रा नहीं, गुणवत्ता नया वर्ष रिश्तों पर भी पुनर्विचार का समय होता है। आज के समय में संपर्क बहुत है, लेकिन संबंध कम। सोशल मीडिया ने हमें जोड़ा तो है, लेकिन दिलों को दूरी भी बढ़ाई है। नया साल यह सोचने का अवसर देता है कि हमारे जीवन में कौन से रिश्ते हमें ऊर्जा देते हैं और कौन से हमें थका देते हैं। हर रिश्ते को निभाना जरूरी नहीं, लेकिन हर रिश्ते को ईमानदारी से निभाना जरूरी है। कुछ रिश्तों को समाप्त देना होता है, कुछ को सीमाएँ और कुछ को सम्मानपूर्वक विदा। नए साल में रिश्तों की सफाई भी उतनी ही जरूरी है जितनी अलमारी की। सफलता की नई परिभाषा

समाज ने सफलता की एक तय परिभाषा बना दी है—पैसा, पद और प्रतिष्ठा। लेकिन नया वर्ष हमें यह सोचने का अवसर देता है कि क्या यही सफलता है? क्या वह व्यक्ति असफल है जो शांत है, संतुष्ट है और अपने मूल्यों पर खड़ा है? सफलता की नई परिभाषा में मानसिक शांति, आत्मसम्मान, स्वास्थ्य और संतुलन भी शामिल होना चाहिए। अगर हम दिन के अंत में चैन से सो पाते हैं, खुद पर अहंसा नहीं करते हैं और किसी के साथ अन्याय नहीं करते—तो यह भी सफलता ही है। असफलता से दोस्ती नए सपनों के साथ नई असफलताएँ भी आती हैं। लेकिन असफलता से डरना नहीं, उससे सीखना जरूरी है। हर असफलता हमें यह बताती है कि कौन सा रास्ता हमारे लिए नहीं है। नया वर्ष हमें यह साहस देता है कि हम फिर से कोशिश करें, बिना खुद को कमतर समझे। जो लोग असफलता से डरते हैं, वे अक्सर प्रयास ही नहीं करते। और जो प्रयास नहीं करते, वे कभी आगे नहीं बढ़ते। नया साल जोखिम लेने और सीखते हुए आगे बढ़ने का नाम है। समाज और जिम्मेदारी नया वर्ष केवल व्यक्तिगत बदलाव का समय नहीं, सामाजिक जिम्मेदारी का भी समय है। हम जिस समाज में रहते हैं, उसकी समस्याओं से हम अछूते नहीं रह सकते। छोटे-छोटे प्रयास—जैसे ईमानदारी, संवेदनशीलता, पर्यावरण के प्रति जागरूकता—समाज को बेहतर बना सकते हैं। अगर हर व्यक्ति नए साल में एक अछूती आदत अपना ले—तो बदलाव अपने आप दिखने लगेगा। निष्कर्ष: नया साल, नया दृष्टिकोण नया वर्ष कोई जादुई छड़ी नहीं है जो सब कुछ बदल दे। बदलाव तब आता है जब हम अपने सोचने का तरीका बदलते हैं। नए सपने, नई उम्मीदें तभी सार्थक हैं जब वे हमें बेहतर इंसान बनाएँ—ज्यादा संवेदनशील, ज्यादा जिम्मेदार और ज्यादा सच्चा। आइए, इस नए वर्ष में हम यह सब संकल्प ले कि हम परिपूर्ण नहीं, लेकिन ईमानदार बनने की कोशिश करेंगे। हम सबसे आगे दिहें, लेकिन सही दिशा में चलने का प्रयास करेंगे। और जब साल के अंत में पीछे मुड़कर देखेंगे, तो गर्व से कह सकें—हाँ, मैंने खुद के साथ ईमानदारी की। यही है नूतन वर्ष का असली अर्थ—नए सपने, नई उम्मीदें और एक बेहतर 'मैं'।

नया वर्ष केवल कैलेंडर की तारीख बदलने का नाम नहीं है। यह हमारे जीवन में एक ठहराव की तरह आता है—जहाँ हम पीछे मुड़कर देखते हैं, वर्तमान को समझते हैं और भविष्य की दिशा तय करते हैं। हर नया साल अपने साथ नई उम्मीदें, नए संकल्प और नई संभावनाएँ लेकर आता है। यह वह क्षण होता है जब मनुष्य अपने भीतर झाँकता है और स्वयं से यह प्रश्न करता है: 'संस्कार में 2026 तक US\$ 500 बिलियन की इकॉनमी के साथ एक समृद्ध ओडिशा बनाने और राज्य को 'मिस्ड इकॉनमी' की ओर ले जाकर इसे टॉप 5 विकसित राज्यों में लाने का लक्ष्य रखा है। इसलिए, मुख्यमंत्री के तौर पर, उन्होंने नॉलेज-ड्रिवन इंडस्ट्रीज और सर्विस सेक्टर को ज्यादा महत्व देकर इसके तेजी से विकास के लिए काम करने का निर्देश दिया है। सभी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरों को राज्य में इंडस्ट्रियलाइजेशन के तेजी से विकास के लिए अलग-अलग प्रोसेस को फास्ट-ट्रैक करने के निर्देशों पर जोर दिया गया है। इसी तरह, उन्होंने अगले 2 साल के अंदर सभी खाली सरकारी पोस्ट भरने का आदेश दिया है। उन्होंने काबिल और ट्रेड अधिकारियों की सर्विस पर जोर दिया है और भ्रष्ट, नाकाबिल और गैर-जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों की पहचान करके उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहा है। उन्होंने कंपलसरी सर्विस बंद करने का भी आदेश दिया है। यह मुख्यमंत्री के एडमिनिस्ट्रेशन को ट्रांसपेरेंट, कुशल और मोबाइल बनाने के पक्के इरादे को दिखाता है। इसके साथ ही, अलग-अलग प्रोजेक्ट्स को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए रेगुलर रिव्यू और इवैल्यूएशन पर जोर दिया गया है। रिसर्च और डेवलपमेंट पर जोर देने के लिए, नवकृष्ण चौधरी डेवलपमेंट रिसर्च सेंटर को सेंटर ऑफ एक्सिलेंस के तौर पर डेवलप करने का आदेश दिया गया है। मुख्यमंत्री ने सभी तरह के सरकारी काम, खासकर नोटिस, नोटिफिकेशन और चिट्ठियों का लेन-देन सिर्फ ओडिशा भाषा में करने का आदेश दिया है। सेक्रेटरीएट से लेकर ब्लॉक लेवल तक के सभी अधिकारियों को इस निर्देश का सख्ती से पालन करने को कहा गया है। शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभागों से इस बारे में माफ़ी मांगने को भी कहा गया है। इसलिए, मुख्यमंत्री ने ओडिशा को ऑफिशियल भाषा के तौर पर इस्तेमाल करने के कमिटेट का भी मैसेज दिया है।

नया वर्ष केवल कैलेंडर की तारीख बदलने का नाम नहीं है। यह हमारे जीवन में एक ठहराव की तरह आता है—जहाँ हम पीछे मुड़कर देखते हैं, वर्तमान को समझते हैं और भविष्य की दिशा तय करते हैं। हर नया साल अपने साथ नई उम्मीदें, नए संकल्प और नई संभावनाएँ लेकर आता है। यह वह क्षण होता है जब मनुष्य अपने भीतर झाँकता है और स्वयं से यह प्रश्न करता है: 'संस्कार में 2026 तक US\$ 500 बिलियन की इकॉनमी के साथ एक समृद्ध ओडिशा बनाने और राज्य को 'मिस्ड इकॉनमी' की ओर ले जाकर इसे टॉप 5 विकसित राज्यों में लाने का लक्ष्य रखा है। इसलिए, मुख्यमंत्री के तौर पर, उन्होंने नॉलेज-ड्रिवन इंडस्ट्रीज और सर्विस सेक्टर को ज्यादा महत्व देकर इसके तेजी से विकास के लिए काम करने का निर्देश दिया है। सभी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरों को राज्य में इंडस्ट्रियलाइजेशन के तेजी से विकास के लिए अलग-अलग प्रोसेस को फास्ट-ट्रैक करने के निर्देशों पर जोर दिया गया है। इसी तरह, उन्होंने अगले 2 साल के अंदर सभी खाली सरकारी पोस्ट भरने का आदेश दिया है। उन्होंने काबिल और ट्रेड अधिकारियों की सर्विस पर जोर दिया है और भ्रष्ट, नाकाबिल और गैर-जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों की पहचान करके उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहा है। उन्होंने कंपलसरी सर्विस बंद करने का भी आदेश दिया है। यह मुख्यमंत्री के एडमिनिस्ट्रेशन को ट्रांसपेरेंट, कुशल और मोबाइल बनाने के पक्के इरादे को दिखाता है। इसके साथ ही, अलग-अलग प्रोजेक्ट्स को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए रेगुलर रिव्यू और इवैल्यूएशन पर जोर दिया गया है। रिसर्च और डेवलपमेंट पर जोर देने के लिए, नवकृष्ण चौधरी डेवलपमेंट रिसर्च सेंटर को सेंटर ऑफ एक्सिलेंस के तौर पर डेवलप करने का आदेश दिया गया है। मुख्यमंत्री ने सभी तरह के सरकारी काम, खासकर नोटिस, नोटिफिकेशन और चिट्ठियों का लेन-देन सिर्फ ओडिशा भाषा में करने का आदेश दिया है। सेक्रेटरीएट से लेकर ब्लॉक लेवल तक के सभी अधिकारियों को इस निर्देश का सख्ती से पालन करने को कहा गया है। शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभागों से इस बारे में माफ़ी मांगने को भी कहा गया है। इसलिए, मुख्यमंत्री ने ओडिशा को ऑफिशियल भाषा के तौर पर इस्तेमाल करने के कमिटेट का भी मैसेज दिया है।

नया वर्ष केवल कैलेंडर की तारीख बदलने का नाम नहीं है। यह हमारे जीवन में एक ठहराव की तरह आता है—जहाँ हम पीछे मुड़कर देखते हैं, वर्तमान को समझते हैं और भविष्य की दिशा तय करते हैं। हर नया साल अपने साथ नई उम्मीदें, नए संकल्प और नई संभावनाएँ लेकर आता है। यह वह क्षण होता है जब मनुष्य अपने भीतर झाँकता है और स्वयं से यह प्रश्न करता है: 'संस्कार में 2026 तक US\$ 500 बिलियन की इकॉनमी के साथ एक समृद्ध ओडिशा बनाने और राज्य को 'मिस्ड इकॉनमी' की ओर ले जाकर इसे टॉप 5 विकसित राज्यों में लाने का लक्ष्य रखा है। इसलिए, मुख्यमंत्री के तौर पर, उन्होंने नॉलेज-ड्रिवन इंडस्ट्रीज और सर्विस सेक्टर को ज्यादा महत्व देकर इसके तेजी से विकास के लिए काम करने का निर्देश दिया है। सभी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरों को राज्य में इंडस्ट्रियलाइजेशन के तेजी से विकास के लिए अलग-अलग प्रोसेस को फास्ट-ट्रैक करने के निर्देशों पर जो

निर्वाचन आयोग द्वारा जारी सूचना : आपकी एक छोटी सी गलती कहीं आपको वोट के अधिकार से वंचित ना कर दे, जाने

पिकी कुं

दिल्ली में SIR (Special Intensive Revision) विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है, जिसमें सभी मतदाताओं को अपना परिगणना फॉर्म भरकर बीएलओ को जमा करवाना होगा। फॉर्म जमा नहीं करवाने पर आपका नाम मतदाता सूची में नहीं आएगा।

उद्देश्य

- मृत व्यक्तियों के नाम हटाना।
- स्थायी रूप से निवास बदलने वालों का नाम हटाना।
- किसी मतदाता का दो स्थानों पर पंजीकरण हो उसे निरस्त करना।
- फर्जी मतदाताओं का नाम हटाना।
- शुद्ध, स्वच्छ व पारदर्शी मतदाता सूचियों का निर्माण करना।

पुनःपंजीकरण प्रक्रिया

* अपना फॉर्म भरने से पूर्व आप अपने 2 नवीनतम रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो जरूर खिंचवा लें, जिसका बैकग्राउंड सफेद होना

चाहिए।

* आप सभी को BLO द्वारा परिगणना फॉर्म उपलब्ध करवाया जाएगा, जिसे निश्चित समय में भरकर BLO को जमा करवाना होगा।

फॉर्म के साथ आपको 11 दस्तावेजों की सूची में से कोई भी दस्तावेज अनिवार्य रूप से संलग्न करना होगा।

दस्तावेजों की सूची

- केंद्र सरकार/राज्य सरकार/PSU के नियमित कर्मचारियों को जारी पहचान पत्र या पेंशन कार्ड
- भारत में 01/07/1987 से पूर्व सरकार/बैंक/LIC/डाकघर/PSU या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र/दस्तावेज/पहचान पत्र
- जन्म प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- 10 वीं बोर्ड की अंक तालिका मय प्रमाण पत्र
- वन अधिकार प्रमाण पत्र

2. यदि आपका जन्म 01/07/1987 से पूर्व हुआ है, तो आपको स्वयं का कोई भी एक दस्तावेज जमा करवाना होगा, साथ में कोई अतिरिक्त दस्तावेज है तो भी काम आएगा, लेकिन कोई एक

दस्तावेज होना अनिवार्य है।

3. यदि आपका जन्म 01/07/1987 से 02/12/2004 के मध्य हुआ है तो आपको एक दस्तावेज स्वयं का तथा एक दस्तावेज माता-पिता का होना अनिवार्य है। यानी कम से कम 2 दस्तावेज होने चाहिए।

4. यदि आपका जन्म 02/12/2004 के बाद हुआ है तो आपके पास 3 दस्तावेज होने चाहिए। एक स्वयं का, एक माता का व एक पिता का। कम से कम तीन दस्तावेज।

SIR प्रक्रिया शुरू होने वाली है, आप अपने परिवार व आसपास के लोगों तक इसकी सूचना पहुंचाएं। उन्हें भी दस्तावेज तैयार करने के लिए प्रेरित करें, जिससे पारदर्शी मतदाता सूचियों का निर्माण हो सके।

आपका वोट आपका अधिकार है। जागरूक मतदाता बनें व परिगणना फॉर्म भरकर अपने BLO को जमा करवाएं।

निर्वाचन आयोग



परिवर्तन का एक दशक: भाजपा-नेतृत्व वाली सरकार के तहत भारत की बहु-क्षेत्रीय प्रगति

संगिनी घोष विशेष संवाददाता परिवहन विशेष

2014 से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकारों के कार्यकाल में भारत ने विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय परिवर्तन देखा है, जिसमें बुनियादी ढांचे के विकास, आर्थिक सुधार, सामाजिक कल्याण और वैश्विक स्तर पर सशक्त उपस्थिति पर विशेष जोर रहा है। राष्ट्रीय राजमार्गों, एक्सप्रेसवे, रेलवे, हवाई अड्डों और शहरी अवसंरचना में बड़े पैमाने पर निवेश से संपर्क व्यवस्था में सुधार हुआ है और आर्थिक गतिविधियों को गति मिली है। क्षेत्रीय हवाई संपर्क जैसी पहलों ने छोटे शहरों को भी राष्ट्रीय विमानन नेटवर्क से जोड़ा है। वहीं, सेमी-हाई-स्पीड ट्रेनों की शुरुआत सहित रेलवे आधुनिकीकरण का उद्देश्य यात्रियों की सुविधा और दक्षता बढ़ाना रहा है।

आर्थिक क्षेत्र में एकीकृत अप्रत्यक्ष कर प्रणाली जैसे संरचनात्मक सुधारों

ने भारत की कर व्यवस्था को नया स्वरूप दिया है, जबकि डिजिटल पहलों ने वित्तीय समावेशन और पारदर्शिता को तेज किया है। डिजिटल भुगतान और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के तेजी से विस्तार ने कल्याणकारी योजनाओं के वितरण को अधिक प्रभावी बनाया है और लीकेज को कम किया है। इसके साथ ही, स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूती मिली है, जिससे भारत नवाचार और उद्यमिता के वैश्विक केंद्रों में शामिल हुआ है, जिसे कारोबार सुगमता बढ़ाने वाली नीतियों का समर्थन मिला है।

सामाजिक कल्याण सरकार की प्राथमिकताओं में प्रमुख रहा है, जिसमें आवास, स्वास्थ्य, स्वच्छता, स्वच्छ ईंधन और वंचित वर्गों के लिए वित्तीय पहुंच से जुड़ी योजनाएं शामिल हैं। व्यापक स्वास्थ्य बीमा कवरेज ने आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए चिकित्सा सुविधाओं तक पहुंच बढ़ाई है, जबकि आवास

और स्वच्छता कार्यक्रमों ने ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में जीवन स्तर सुधारने का प्रयास किया है। विशेष रूप से स्वच्छ ऊर्जा और वित्तीय समावेशन से जुड़ी महिला-केंद्रित पहलों को सामाजिक सशक्तिकरण की दिशा में कदम के रूप में देखा गया है।

रक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में स्वदेशी निर्माण और आधुनिकीकरण पर जोर दिया गया है, जिससे आयात पर निर्भरता कम करने और रणनीतिक आत्मनिर्भरता बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। सैन्य नेतृत्व संरचना में सुधार और मजबूत सुरक्षा नीति को तैयारियों को सुदृढ़ करने के उपाय के रूप में प्रस्तुत किया गया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी, विशेषकर अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत की उपलब्धियों ने वैश्विक स्तर पर ध्यान आकर्षित किया है और अनुसंधान व नवाचार में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाया है।

वैश्विक मंच पर भारत की कूटनीतिक सक्रियता में वृद्धि हुई है, बहुपक्षीय मंचों में सक्रिय भागीदारी के साथ अंतरराष्ट्रीय निर्णय-प्रक्रियाओं में देश की आवाज और मजबूत हुई है। सांस्कृतिक और विरासत से जुड़ी पहलों के साथ-साथ योग के वैश्विक प्रचार को भारत की सॉफ्ट पावर का हिस्सा बताया गया है। वहीं, नवीकरणीय ऊर्जा के विस्तार और देशव्यापी स्वच्छता अभियानों जैसे पर्यावरण और सतत विकास से जुड़े प्रयासों को दीर्घकालिक विकास की दिशा में कदम माना गया है।

कुल मिलाकर, ये सभी विकासक्रम पहले सुधार, बुनियादी ढांचा आधारित विकास, कल्याणकारी योजनाओं की प्रभावी पहुंच और वैश्विक सहभागिता पर केंद्रित शासन दृष्टिकोण को दर्शाती हैं, जिसने पिछले एक दशक में भारत की विकास यात्रा को आकार दिया है।

टाटा स्टील का स्ट्रैट बार मिल 31 दिसंबर को अचानक हुआ बंद, 700 लोग हुए बेरोजगार



कार्तिक कुमार परिच्छा, स्टेट हेड - झारखंड

जमशेदपुर, झारखंड के सरायकेला जिला अन्तर्गत महत्वपूर्ण क्षेत्र आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र स्थित टाटा स्टील की इकाई स्ट्रेट बार मिल (पूर्व में उषा मार्टिन) बुधवार 31 दिसंबर से अचानक बंद कर दी गयी। इसके साथ ही करीब 700 कामगार बेरोजगार हो गए। इसकी खबर मिलते ही कामगार आक्रोशित हो गये और मिल गेट पर प्रदर्शन किया। बुधवार सुबह ड्यूटी पर कामगार

पहुंचे तो कंपनी बंद की सूचना से भड़क गये। गेट पर हंगामा के साथ प्रदर्शन शुरू कर दिया। कर्मचारियों ने प्रबंधन पर बिना सूचना के बंद करने का आरोप लगाया। बताया कि वर्ष 1999 से कई कामगार यहाँ कार्यरत हैं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया। अब इस उम्र में उन्हें कहां नौकरी मिलेगी। कंपनी बंद करने से पूर्व उनका बकाया वेतन समेत अन्य सुविधाओं का भी भुगतान नहीं किया गया है। टाटा स्टील की ओर से जब उषा मार्टिन के इस प्लांट का अधिग्रहण किया था, तब यह भरोसा

दिया गया था कि प्लांट का संचालन जारी रहेगा। साथ ही किसी की नौकरी नहीं जाएगी। वर्तमान में यह प्लांट वेंडर कंपनी आरके एंटरप्राइजेज के माध्यम से संचालित हो रही थी, जिसके तहत 165 श्रमिक कार्यरत थे। वहीं, अन्य ठेकेदारों के अधीन कार्यरत कामगारों को मिलाकर करीब 6 सौ से अधिक बेरोजगार हो गए हैं। कामगारों ने बताया कि उनकी तीन प्रमुख मांगों में कंपनी को चलाने, बंद करने की स्थिति में अन्य कंपनियों में वर्तमान पे स्केल में समायोजित करने एवं 31 दिसंबर तक के सभी

कामगारों का वेतन, ग्रेज्युटी एवं अन्य सुविधाओं का अविरोध भुगतान शामिल हैं। इस संदर्भ में वेंडर कंपनी आरके एंटरप्राइजेज के प्रोपराइटर राजेश कुमार ने बताया कि पिछले एक साल से उनके अधीन कार्यरत कामगारों की बकाया राशि का भुगतान करने को तैयार हैं। लेकिन, पूर्व से कार्यरत कामगारों की बकाया राशि के भुगतान के लिए वे जिम्मेवार नहीं हैं। उन्होंने कहा कि कंपनी बंद होने के साथ ही उनका वेंडर का कॉन्ट्रैक्ट भी 31 दिसंबर को समाप्त हो गया।

नया साल हमें सिखाता है कि हर अंत नई शुरुआत है

डॉ. मुश्ताक अहमद शाह सहज

रुद्रा मध्य प्रदेश

नया साल आया और पुराना साल चला गया। कैलेंडर के पन्ने पलटें, लेकिन मन में एक सदात कौंध उठा, जीवन का एक वर्ष फिर कम हो गया। क्या यही छिटकी है कि हम बस मृत्यु की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं? यह विचार उदासीनता की छाया डाल सकता है, पर सकारात्मक सोच इसे एक नई रोशनी में बदल देती है। जीवन को मृत्यु की ओर यात्रा मानने का अर्थ है, इसे एक अन्वेषण की तरह देखें, हर पल नई संभावनाओं से भरा धार्य: लोग अपने जीवन के पलों को नकारात्मक रखने से

देखते हैं। कल की धिंता, भविष्य का डर, और गुजरे लम्हों का पछतावा, ये सब मिलकर वर्तमान को ग्रीका कर देते हैं। लेकिन सकारात्मक सोच कहती है: "जीवन एक रंग है, मंत्रिल नहीं।" उम्र वाले 20 को रो या 80 की, हर पल को जीना सीखें। आयुर्वेद की दृष्टि से भी, जीवन को 'जीवन' ही कहते हैं—मिथो, बढ़ो, फलो। योग और नेचुरोपैथी हमें सिखाते हैं कि श्वास के साथ हर क्षण को स्वीकार करो। हर पल को वर्तमान में ग्रिपो, अतीत को संभक उन्नम, भविष्य का सपना देखो। आज के पल को पूर्णता से अनुभव करो। सुबह की पहली वायु, शाम की सैर, या प्रियजनों की हंसी, उन्हे संजो

तो कृतज्ञता का अभ्यास करो, रोज तीन चीजें लिखो जिनके लिए आभारी हो। यह छोटी आदत दिमाग को सकारात्मक तरंगों से भर देगी। जैसे, नया साल हमें याद दिलाता है कि हम अभी भी सांस तो रहे हैं, यह अपने आप में आशीर्वाद है। छोटे लक्ष्य बनाओ, उम्र कोई बाधा नहीं। 150 में भी नई करियां लिखो, योग सीखो, या परिवार के साथ घूम आओ। हर दिन एक नया 'शेर' खो, जैसे उर्दू शायरी में जीवन को 'बहार' कहते हैं सकारात्मक संज्ञाति चुनो, ऐसे लोग साथ रखो जो प्रेरित करें। भारतीय संस्कृति में 'सत्सेव' की परंपरा यही सिखाती है, सकारात्मक ऊर्जा जीवन को जीवंत बनाती है। स्वास्थ्य पर

ध्यान दीजिए, आयुर्वेद बताता है, संतुलित आहार, प्रणामाग और ध्यान से हर उम्र में ताजगी बनी रहती है। मृत्यु को उरना छोड़ो, जीवन को लो लम्बाओ। जीवन की यह यात्रा सीधी रेखा नहीं, बल्कि घुमावदार राह है। नया साल हमें सिखाता है कि हर अंत नई शुरुआत है। सकारात्मक सोच प्रगति को एक वर्ष कम लेना नहीं, बल्कि अनुभवों का खजाना बढ़ाना लगेगा। हर पल को जीयो, जैसे कोई अज्ञात, हर भ्रमरा नया रंग भरे। उम्र बस अंक है, छिंददिली अस्सी भावदंड। तो आज से संकेत लो, हर सांस को उत्सव बनाओ। नया साल नुबाकर नहीं, हर दिन नया साल लो!

खरसावां गोलीकांड के शहिदों को श्रद्धांजलि देने मुख्यमंत्री हेमंत पहुंचे शहीद पार्क

कार्तिक कुमार परिच्छा, स्टेट हेड - झारखंड

खरसावां, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुजरात को सरायकेला-खरसावां जिले के शहीदों को श्रद्धांजलि खरसावां में दी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा- अब सरकार ने यह निर्णय लिया है कि खरसावां के शहीदों के परिवार को हम ढूंढेंगे और उन्हें सम्मान देंगे। उसके लिए एक कमेटी गठित करने का निर्णय लिया गया है।

1948 के गोलीकांड में शहीद हुए लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा, सांसद जीवा मांझी सहित कई विधायक और राजनीतिक-सामाजिक संगठनों के दिग्गज नेता पहुंचे।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा- आज के खरसावां के इस शहीद स्थल पर इतना बड़ा जनसंघर्ष और यहां पर लोगों का जमावड़ा, किसी से छुपा नहीं है। आज का यह दिन खरसावां के शहीदों को नमन करने के लिए कोल्हान ही नहीं राज्य के कोने-कोने से लोग यहां आते हैं। हमारे आदिवासियों में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा- आज के खरसावां के इस शहीद स्थल पर इतना बड़ा जनसंघर्ष और यहां पर लोगों का जमावड़ा, किसी से छुपा नहीं है। आज का यह दिन खरसावां के शहीदों को नमन करने के लिए कोल्हान ही नहीं राज्य के कोने-कोने से लोग यहां आते हैं।

हमारे आदिवासियों, समुदाय के वीरों ने यहां के आदिवासियों,



मूलवासियों के हक अधिकार। यहां के जल, जंगल, जमीन के लिए अपने को कुर्बान कर दिया। यह स्थल इतिहास के पन्नों का वह हिस्सा है, जो ना ही भूलने वाला है और ना कभी खत्म होने वाला है।

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खरसावां गोलीकांड के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। - Dainik Bhaskar मुख्यमंत्री ने कहा- आज हमलोग हर साल की भांति इस साल भी शहीदों को याद करने के लिए, उनको नमन करने के लिए,

उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित हुए हैं। चूंकि अबुआ सरकार है और आप लोगों को याद होगा कि हमने किस प्रकार गुवा के शहीदों के परिवार को ढूंढा था।

अब सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि खरसावां के शहीदों के परिवार को हम ढूंढेंगे। इससे जुड़े आंदोलन से जुड़े लोगों को भी ढूंढेंगे। उसके लिए एक कमेटी गठित करने का निर्णय लिया गया है। जो बहुत जल्द अपना काम शुरू करेगी। उन्होंने कहा- जैसे गुवा शहीद के

परिवार को सम्मान देने का काम किया है। उसी प्रकार खरसावां गोलीकांड के शहीदों के परिवार को सम्मान देंगे।

शहीद दिवस कार्यक्रम के दौरान विधि-व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए जगह-जगह जवानों की तैनाती की गई है। शहीद दिवस को ले कर खरसावां चांदनी चौक से सरायकेला, आमदा, कुचाई और हुडगंदा मार्गों में विभिन्न जगह लोगों का जमावड़ा रहा।

2 जनवरी उनके शहादत दिवस पर विशेष प्रतिरोध की अमर आवाज सफदर हाशमी

शम्भूशरण सत्यार्थी

सफदर हाशमी का जीवन भारतीय रंगमंच के इतिहास में एक ऐसे उज्ज्वल अध्याय की तरह दर्ज है, जहाँ कला, विचार और संघर्ष एक-दूसरे से अलग नहीं, बल्कि एक-दूसरे में घुले हुए दिखाई देते हैं। वे केवल एक रंगमंच नहीं थे, बल्कि जनसंघर्ष की चेतना से लैस ऐसे सांस्कृतिक योद्धा थे, जिन्होंने यह सिद्ध किया कि जब कला जनता के पक्ष में खड़ी होती है, तो वह सत्ता के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाती है। उनका जीवन और उनकी शहादत—दोनों इस बात के प्रमाण हैं कि सच्ची कला हमेशा असुविधाजनक होती है, क्योंकि वह प्रश्न पूछती है, चुपचाप तोड़ती है और अन्याय को बेकाबू करती है।

12 अप्रैल 1954 को दिल्ली में जन्मे सफदर हाशमी को विरासत में साहित्य और प्रातिशिल चेतना मिली। उनके पिता हाईमद हाशमी उर्दू के जाने-माने प्रातिशिल कवि थे और अत्यायक को बेकाबू करती थीं। घर का वातावरण साहित्यिक बहसों, सामाजिक सरोकारों और वैचारिक प्रतिबद्धता से भरा हुआ था। यही कारण था कि सफदर बचपन से ही केवल अपने

आसपास की दुनिया को देखने वाले नहीं, बल्कि उसे समझने और बदलने की आकांक्षा रखने वाले व्यक्ति बने। दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफेंस कॉलेज से अंग्रेजी साहित्य की पढ़ाई के दौरान उनके भीतर रंगमंच के प्रति गहरी रुचि विकसित हुई, लेकिन यह रुचि पारंपरिक मंचीय अभिनय तक सीमित नहीं थी। सफदर ने बहुत जल्दी यह महसूस कर लिया कि सनगारों में सिमटा रंगमंच आम जनता से कटता जा रहा है। उन्होंने लामे लामा किजस समाज में अस्मानता, विस्तार था। उनका पत्नी मोलीयश्री हाशमी स्वयं एक अमर कलाकार का दायित्व था कि वह अन्याय के विरुद्ध स्पष्ट पक्ष ले, चाहे उसकी कीमत कुछ भी हो। उनका निजी जीवन भी इसी सादगी और प्रतिबद्धता का विस्तार था। उनका पत्नी मोलीयश्री हाशमी स्वयं एक संवेदनशील लेखिका और सांस्कृतिक कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने सफदर के बाद जनम और सांस्कृतिक प्रतिरोध की परंपरा को आगे बढ़ाया।

1 जनवरी 1989 भारतीय सांस्कृतिक इतिहास का एक दुःखद और निर्णायक दिन बन गया। गाँजियाबाद के साहित्यवादी में जनम के कलाकार 'हल्ला बोल' नाटक का मंचन कर रहे थे, जो स्थानीय राजनीतिक

नाटक को एक सशक्त राजनीतिक और सांस्कृतिक माध्यम के रूप में स्थापित किया। सड़क, चौराहा, फैक्ट्री गेट और बस्ती—यही उनका रंगमंच था। बिना मंच, बिना रोशनी और बिना परदे के खेले जाने वाले उनके नाटक सीधे जनता से संवाद करते थे। उनके लिए दर्शक कोई निष्क्रिय उपभोक्ता नहीं था, बल्कि एक सक्रिय सहभागी था, जो नाटक के सवालों से टकराता था। 'मशीन', 'हल्ला बोल', 'औरत', 'दस्तक', 'जानता पागल हो गई है' जैसे नाटकों ने श्रमिक शोषण, पूँजीवादी लूट, साम्प्रदायिकता, पितृसत्ता और राज्य के दमनकारी चरित्रों को बेहद सहज लेकिन तीखे अंदाज में उजागर किया।

सफदर ने नाटकों की भाषा सरल थी, पर उसमें गहरी वैचारिक धार थी। वे न तो जटिल प्रतीकों के बोझ तले दबे होते थे और न ही उपदेशात्मक। उनके व्यंग्य में करुणा थी और उनके प्रतिरोध में मानवीय संवेदन। वे मानते थे कि जननाट्य का उद्देश्य केवल गुस्सा पैदा करना नहीं, बल्कि चेतना जगाना है। यही कारण है कि उनके नाटक आज भी उनसे ही प्रासंगिक लगते हैं, जितने अपने समय में थे।

सफदर हाशमी केवल रंगमंच तक सीमित नहीं थे। वे एक गंभीर लेखक और चिंतक भी थे। कला और संस्कृति पर उनके लेख यह स्पष्ट करते हैं कि वे तटस्थता को एक प्रकार की कार्यरता मानते थे। उनका प्रसिद्ध कथन— "संस्कृति कभी तटस्थ नहीं होती" — आज भी सांस्कृतिक विमर्श का केंद्रीय सूत्र है। उनके लिए कलाकार का दायित्व था कि वह अन्याय के विरुद्ध स्पष्ट पक्ष ले, चाहे उसकी कीमत कुछ भी हो। उनका निजी जीवन भी इसी सादगी और प्रतिबद्धता का विस्तार था। उनका पत्नी मोलीयश्री हाशमी स्वयं एक संवेदनशील लेखिका और सांस्कृतिक कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने सफदर के बाद जनम और सांस्कृतिक प्रतिरोध की परंपरा को आगे बढ़ाया।

1 जनवरी 1989 भारतीय सांस्कृतिक इतिहास का एक दुःखद और निर्णायक दिन बन गया। गाँजियाबाद के साहित्यवादी में जनम के कलाकार 'हल्ला बोल' नाटक का मंचन कर रहे थे, जो स्थानीय राजनीतिक

हिंसा और गुंडागर्दी के खिलाफ था। सत्ता-संरक्षित अपराधियों ने नाटक के दौरान हमला कर दिया। सफदर हाशमी को लोहे की रॉड से बेहमीसी से पीटा गया और अगले दिन, 2 जनवरी 1989 को, 34 वर्ष की उम्र में उन्होंने दम तोड़ दिया। यह केवल एक कलाकार की हत्या नहीं थी, बल्कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सीधा हमला था।

सफदर की शहादत ने पूरे देश को झकझोर दिया। कलाकारों, लेखकों और आम नागरिकों ने महसूस किया कि अगर सड़क पर सच बोलने वाला कलाकार सुरक्षित नहीं है, तो लोकतंत्र भी सुरक्षित नहीं है। उनकी हत्या के ठीक बाद उसी जगह जनम ने फिर नाटक खेला—यह घोषणा करते हुए कि विचारों को लाठियों से कुचला नहीं जा सकता। यही क्षण सफदर हाशमी को एक व्यक्ति से प्रतीक में बदल देता है—प्रतिरोध के प्रतीक में।

आज सफदर हाशमी हमारे बीच शारीरिक रूप से नहीं हैं, लेकिन उनकी उपस्थिति हर उस नुक़ड़ पर महसूस की जा सकती है, जहाँ कोई कलाकार सत्ता से सवाल करता है। उनके नाम पर गठित 'सफदर हाशमी मेमोरियल ट्रस्ट' (सहमत) संप्रदायिकता, फासीवादी प्रवृत्तियों और सांस्कृतिक दमन के विरुद्ध लगातार सक्रिय है। सफदर की विरासत यह सिखाती है कि कला का असली मूल्य उसकी बाजार सफलता में नहीं, बल्कि उसकी जनपक्षरता में है।

ऐसे समय में, जब कला को लाप, टीआरपी और प्रायोजकों की शर्तों में बाँधने की कोशिशें तेज हैं, सफदर हाशमी और भी अधिक प्रासंगिक हो जाते हैं। उनका जीवन हमें यह दिलाता है कि कलाकार होना केवल प्रतिभा का प्रश्न नहीं, बल्कि साहस, ईमानदारी और प्रतिबद्धता का प्रश्न भी है। सफदर हाशमी का जीवन भले ही छोटा रहा हो, लेकिन उसका प्रभाव आसधारण रूप से व्यापक है। वे आज भी हमें पुकारते हैं—अन्याय के विरुद्ध, चुपकी के विरुद्ध और डर के विरुद्ध—

हल्ला बोल।

—शम्भूशरण सत्यार्थी